● वर्ष-3
● अंक-298
रायपुर, शुक्रवार
26 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› शिमला की सैर

दवा- उपकरण खरीदी में अनियमितता का मामला, मंत्री ने कहा- समिति कर रही जांच

भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को दवा और उपकरण खरीदी में अनियमितता का मामला गूंजा. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. क्या इसकी जांच कराई जाएगी? स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि तीन आईएएस अधिकारियों की समिति जांच कर रही है. तीन महीने के भीतर जांच कराई जाएगी.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि सीजीएमएससी ने दवा और मेडिकल उपकरण की खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है. एजी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस पर आपत्ति जताई थी. नियमों के विरुद्ध बाजार दर से अधिक कीमत पर खरीदी की गई. बिना मांग सरकारी अस्पतालों में जांच किट भेजी गई. तीस से अधिक जिलों में बगैर डिमांड के रिएजेंट भेज दिया गया. इसकी ख़रीदी कई गुना अधिक दर पर की गई. लगातार शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि खुली निविदा जारी कर सीजीएमएससी ने दवा और उपकरण की ख़रीदी की है. एजी रिपोर्ट आने के बाद तथ्य देकर विभाग उसका निराकरण करता है. अन्य राज्यों के कारपोरेशन की दरों की तुलना कर खरीदी का दर तय किया जाता है. पिछले तीन सालों में बगैर डिमांड के खरीदी नहीं की गई है.

उन्होंने कहा कि हमर लैब में लगने वाले एनालाइजर और रिएजेंट की खरीदी डिमांड आने के बाद ही की गई है. रिएजेंट कालातीत नहीं हुए है. राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिएजेंट के खराब होने का आरोप सत्य नहीं है. ऑटो एनालाइजर मशीन की खरीदी कई गुना दर पर खरीदी का आरोप भी सही नहीं है. खुली निविदा कर एल वन प्राप्त होने के बाद ही खरीदी की गई है. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि ये अरबों रुपए के घोटाले का मामला है. 12- 13 दिसंबर 1022 को एजी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत किसने की थी? किन-किन लोगों के खिलाफ शिकायत हुई थी. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सीएजी की ऑडिट सतत् चलने वाली प्रक्रिया है. अब तक कुल 25 शिकायत प्राप्त हुई हैं, इनमें से 15 शिकायतों का निराकरण हो गया है. दस शिकायते प्रक्रियाधीन हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जैसे मोबाइल है एपल. इसके कई वेरियेंट होते हैं. वेरियेंट के हिसाब से उसकी दर तय होती है. इसी तरह अलग-अलग वेरियेंट की ख़रीदी उसके स्पेसिफ़िकेशन के आधार पर ख़रीदी होती है. जेम पोर्टल पर दिखाए जाने वाले स्पेसिफ़िकेशन और क्वालिटी में अंतर होता है. गुण-दोष का अंतर है. कौशिक ने कहा कि गुण-दोष का अंतर नहीं है. यहाँ कमीशन का मसला है.

विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि जहां ज़रूरत भी नहीं थी. उन जगहों के लिए भी डिमांड भेजी गई. सप्लायर डिमांड क्रियेट कराते हैं. उसके बाद डिमांड भेजी जाती है. ऐसे प्रकरणों की क्या ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाएगी? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि तीन आईएएस अधिकारियों की टीम इस प्रकरण की जांच कर रही है.

कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक बहुमत से पारित

विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2024 बहुमत से पारित हुआ. विपक्ष ने संशोधन विधेयक पर मत विभाजन की मांग की थी, जिसके बाद हुए मतदान में विधेयक के पक्ष में 47 और विपक्ष में 27 मत पड़े. इसके साथ ही सदन में संशोधन विधेयक पारित हो गया.

इससे पहले संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मंडी फीस के जगह कृषक कल्याण कह दिया. जियो जब शुरू हुआ तो फ्री में दिया गया था. आज पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा कब्जा इनका है, और अब सबसे महंगा यही है. हिमाचल में क्या हुआ. वही बड़े लोग रेट खोल रहे हैं. औने-पौने दाम में हिमाचल में सेव बेचने के लिए किसान मजबूर हैं.

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सदस्यों ने कई तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं. आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी सरकार किसानों के हित की चिंता नहीं करेगी. भूपेश बघेल तो ऐसा बोलने लगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग आ जाएंगे. मंडी अधिनियम में पशुपालन, मछलीपालन शामिल नहीं है. इसके बावजूद यदि कहीं भी यदि इसके परीक्षण की जरूरत होगी तो परीक्षण कराऊंगा. यदि ऐसा कुछ होगा तो इसे संशोधन से बाहर करूंगा.

नगरीय निकाय चुनाव से पहले हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

वार्ड परिसीमन पर लगाई रोक

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने निकायों के वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी है, याचिकाकर्ताओं ने वार्डों के परिसीमन को नियम के विरुद्ध बताया था। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को झटका लगा है। मामले में अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद तय की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया है।

दरअसल, राजनादगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका व बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों के परिसीमन को लेकर चुनौती दी गई थी। तीनों याचिकाओं की प्रकृति समान थी, इसलिए कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को एक साथ मर्ज करते हुए सुनवाई शुरू की। मामले में याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में बताया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है, उसमें वर्ष 2011 के जनगणना को आधार माना है। वार्ड परिसीमन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अंतिम जनगणना को आधार माना गया है। राज्य सरकार ने अपने सर्कुलर में भी परिसीमन के लिए अंतिम जनगणना को आधार माना है। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं का तर्क था कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया है। जब आधार एक ही है तो इस बार क्यों परिसीमन का कार्य किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के इस तर्क पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने पूछा, कि वर्तमान में वर्ष 2024 में फिर से परिसीमन क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर वर्ष 2014 व 2019 में वार्डों का परिसीमन किया गया था। जनगणना का डेटा तो आया नहीं है, वर्ष 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, फिर उसी जनगणना को आधार मानकर तीसरी मर्तबे परिसीमन कराने की जरुरत क्यों पड़ रही है। प्रदेश के निकायों के परिसीमन के बाद दावा आपत्ति मंगाने का काम किया जा रहा था। इस आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया पर रोक लग गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व एजी सतीशचंद्र वर्मा, अमृतो दास, रोशन अग्रवाल और राज्य की ओर से प्रवीण दास उप महाधिवक्ता व विनय पांडेय व नगर पालिका कुम्हारी की तरफ से पूर्व उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की।

तीरंदाजः महिलाओं के बाद पुरुष टीम भी क्वार्टरफाइनल में पहुंची

भारतीय तीरंदाज रैंकिंग और क्वालिफाइंग राउंड के लिए लेस इनवालिडेस गार्डेस में उतरे हैं। पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक आगाज 26 जुलाई से होने जा रहा है, लेकिन तीरंदाजी के क्वालिफाइंग दौर एक दिन पहले शुरू हो गया है। पुरुष और महिला तीरंदाजी टीम आज क्वालिफाइंग/रैंकिंग दौर में उतरी है। इस दौर से तीरंदाजी की पांच स्पर्धाओं (पुरुष, महिला टीम और व्यक्तिगत मुकाबले और मिश्रित टीम स्पर्धा) का रास्ता तैयार हो जाएगा।

डेंगू, मलेरिया और डायरिया पर स्थगन

डेंगू, मलेरिया और डायरिया के बढ़ते मामले पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में चर्चा की मांग की. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश भर की हालत बेहद ख़राब है. अस्पतालों में दवा नहीं है. सरकारी अस्पतालों में जांच की व्यवस्था नहीं है. गरीब परिवार के लोग मलेरिया और डायरिया से ज्यादा पीड़ित हैं. गरीबों को कहा जा रहा है कि प्राइवेट लैब से जांच करा ले. कई मरीज़ों की मृत्यु हो गई है. कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे ज़िले में ही पांच सौ से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं. चार लोगों की मौत हो गई है. मलेरिया और डेंगू से दो लोगों की मौत हो गई है. अस्पतालों में बेड नहीं होने की बात कहकर मरीजों को वापस भेज दिया जा रहा है. स्थिति बेहद भयावह है. कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि कबीरधाम ज़िले के बोडला ब्लॉक में बैगा जाति के पांच लोगों की डायरिया से मौत हो गई है. भाजपा विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि मैनपुर में भी मलेरिया से मौत हुई है. कमार भुइयाँ जनजाति के लोग इस इलाक़े में रहते हैं. ये इलाक़ा हीरा खदान वाला है. अमीर धरती के ग़रीब लोग इस क्षेत्र में रहते हैं. इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों से इन्हें रिफ़र किया जा रहा है.

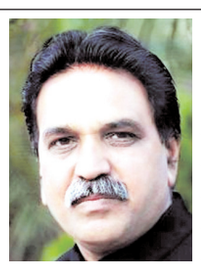

कमल विहार का मामला सदन में गूंजा

विधानसभा सत्र के चौथे दिन कमल विहार का मामला उठा. पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने लैंड यूज बदले बिना टेंडर निकालने का मामला उठाया. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि 2021 के मास्टरप्लान में सिटी पार्क को बाद के मास्टरप्लान में आमोद-प्रमोद कर दिया गया था. भाजपा विधायक राजेश मूणत के सवाल पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2021 के मास्टरप्लान में सिटी पार्क लैंड यूज था. टाउन प्लानिंग स्कीम के स्वीकृत प्लान के मुताबिक़ पार्क स्वीकृत किया गया था. इससे 40 लाख रुपये फंड रेसिंग का भी प्रावधान था. 2021 के मास्टरप्लान में सिटी पार्क था. इसके बाद के मास्टरप्लान में आमोद-प्रमोद कर दिया गया. बेस प्राइज़ से ज़्यादा दर पर श्री जी कृपा नाम के फर्म ने 72 करोड़ रुपये में बीड किया था. लैंड यूस फर्म को करना था, लेकिन उसने आरडीए से किए जाने की मांग को लेकर कमर्शियल कोर्ट में चला गया. यह मामला आर्बिट्रेशन में चल रहा है. राजेश मूणत ने कहा कि रिक्रियेशनल पार्क बनाने टेंडर निकाल लिया. पिछली सरकार के मंत्री ने फाइल अपने पास रख ली थी. रिक्रियेशनल पार्क के नाम पर मैरिज पैलेस नहीं बनाया जा सकता.

प्रमुख समाचार

लोकसभा-विधानसभा चुनाव में हुई बूथ कैप्चरिंग

नई दिल्ली। आज राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, कि हाल ही में हुए संसदीय और विधानसभा चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग की 925 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से सबसे अधिक 875 पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुईं। चुनाव आयोग की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इन मामलों में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कानून मंत्री ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जहां हाल ही में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हुए थे और इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था। पूर्वी कामेंग जिले के खेनवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और एक व्यक्ति अभी भी न्यायिक हिरासत में है। कानून मंत्री ने आगे बताया कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग के लिए 47 शिकायतें दर्ज की गईं।

तो खत्म हो जाएंगे हिंदू, झारखंड की हालत पर बोले निशिकांत दुबे

नई दिल्ली। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने का आह्वान करते हुए कहा कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, और यह भी मांग की कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए, गोड्डा सांसद ने यह भी कहा कि उनके गृह राज्य में आदिवासी आबादी 10 प्रतिशत कम हो गई है और आदिवासी महिलाएं बांग्लादेशी पुरुषों से शादी कर रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ झामुमो आदिवासी आबादी में गिरावट को संबोधित करने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है। दुबे ने कहा कि मैं संथाल परगना क्षेत्र से आता हूं - जब 2000 में संथाल परगना बिहार से अलग हो गया और झारखंड का हिस्सा बन गया, तो 2000 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36% थी। आज इनकी आबादी 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गये? यह सदन कभी उनकी चिंता नहीं करता, वोट बैंक की राजनीति करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी राज्य सरकार झामुमो और कांग्रेस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

देशद्रोही जैसा आचरण कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को खालिस्तानी नेता और अलगाववादी अमृतपाल सिंह को जेल में बंद करने को आपातकाल जैसी स्थिति से जोड़कर विवाद पैदा कर दिया। बजट पर लोकसभा में बोलते हुए, चन्नी ने एनडीए के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना की और कहा कि पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से लगभग 20 लाख लोगों द्वारा एक स्वतंत्र सांसद के रूप में चुने गए वारिस पंजाब दे प्रमुख अपने विचार वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर अब भाजपा कांग्रेस सांसद पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि एक पूर्व सीएम देशद्रोही जैसा आचरण कर रहे हैं और सदन के माध्यम से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि चन्नी के बयान पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी था और कांग्रेस खालिस्तानी का समर्थन कर रही है। वाह रे कांग्रेस, जय चन्नी। यह भारत की संप्रभुता पर हमला है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

टूडो को मिली धमकी तो बौखलाया, खालिस्तानियों पर चुप्पी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ ऑनलाइन धमकियों के लिए दो लोगों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने के बाद भारत ने कनाडा पर दोहरे मानकों का आरोप लगाया है। राष्ट्र भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने वाले खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रहा है। कनाडा द्वारा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं को ऑनलाइन धमकी देने के लिए दो व्यक्तियों पर आरोप लगाए जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने ये रिपोर्ट देखी हैं। जब कोई लोकतंत्र कानून के शासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मापने के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाता है, तो यह केवल उसके दोहरे मापदंड को ही उजागर करता है। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिन्होंने बार-बार भारतीय नेताओं, संस्थानों, एयरलाइनों और राजनयिकों को हिंसा के द्वारा धमकाने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि हमें मिलने वाली धमकियों पर भी उसी स्तर की कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगा.

जोशी ने की राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश

नई दिल्ली। राज्य में पांच विधानसभा क्षेत्रों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी में नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। अभी तीन हफ्ते पहले ही राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करके सभी को चौंकान दिया था। अब सूत्रों ने 25 जुलाई को पुष्टि की कि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों ने कहा कि राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने एक व्यक्ति, एक पद के तहत इस्तीफे की पेशकश की है। हालाँकि, ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि सीपी जोशी के इस्तीफे को राज्य की पांच सीटों पर उपचुनाव से पहले जातिगत समीकरणों के लिए पार्टी के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें झुंझुनू, दौसा, देवली-उनियारा, खींवसर और चौरासी शामिल हैं। इस बीच, यह ध्यान रखना उचित है कि यह पहली बार नहीं है कि भाजपा राजस्थान अध्यक्ष ने पद से अपना इस्तीफा देने की पेशकश की है।

लोकसभा में तीखी नोकझोंक का दौर, मोदी सरकार पर विपक्ष ने लगाया आरोप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में फिर से शुरू हुई। विपक्ष बजट के खिलाफ आज भी सरकार पर हमलावर रहा। हालांकि, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से गुरुवार को संसद के बजट सत्र में बजट पर चर्चा पर कायम रहने का आग्रह किया। संसद का मानसून 22 जुलाई को शुरू हुआ और 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है। लोकसभा में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं, भाजपा सांसद अरुण सागर ने बसपा संस्थापक दिवंगत कांशीराम को मरणोपरांत 'भारत-रत्न' से सम्मानित करने की मांग लोकसभा में उठाई।

लोकसभा में बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और हंगामा बढ़ने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए आरोप लगाया, ''इनमें (सत्तापक्ष) और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रंग का फर्क है। पहले ये सत्ता में काबिज हुए और फिर सत्ता के रास्ते ये देश के उद्योगों पर अपने लोगों का कब्जा करा रहे हैं।'' इस पर रेल राज्य मंत्री और पूर्व कांग्रेस सदस्य बिट्टू ने कुछ टिप्पणी की। जवाब में चन्नी ने उनका नाम लेते हुए कहा, ''आपके पिताजी शहीद हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह उस दिन मरे, जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा।'' इस पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने कांग्रेस सदस्य से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करने को कहा। बिट्टू ने कहा, ''इन्होंने (चन्नी ने) मेरा नाम लिया। मेरे दादा सरदार बेअंत सिंह ने कुर्बानी देश के लिए दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं दी थी।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''चन्नी अपने भाषण में गरीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे पंजाब में अगर ये सबसे अमीर और सबसे भ्रष्ट आदमी नहीं हुए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा।''

एक बार के स्थगन के बाद जब कार्यवाही अपराह्न दो बजे आरंभ हुई तो रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों तरफ के सदस्यों के भाषणों को देखा जाए और जो भी असंसदीय है उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए। बिरला ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में कहा, ''कोई भी सदस्य और मंत्री जी विशेष रूप से सदन की गरिमा को कम नहीं करें। कुछ भी टिप्पणी करनी है, कोई

विषय उठाना है, आप चैम्बर में आकर मिलें।'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना और बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ने तथा हिंदुओं के गांव खाली होने का दावा करते हुए सरकार से इन क्षेत्रों को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की।

तृणमूल कांग्रेस ने 2024-25 के केंद्रीय बजट को 'कॉपी-पेस्ट' और 'एबी' (आंध्र प्रदेश-बिहार) बजट बताते हुए लोकसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि ''केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई अर्थशास्त्री नहीं हैं और वह प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर बजट बनाती हैं।'' तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने 'वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर आगे की सामान्य चर्चा' में हिस्सा लेते हुए कहा कि वह बजट को लेकर सरकार के खिलाफ पार्टी सदस्य अभिषेक बनर्जी के आरोपों से सहमत हैं। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा और उसने टोल राजस्व आदि के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने की योजना बनाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। लोकसभा के कुछ सदस्यों द्वारा बृहस्पतिवार को अधिक हवाई किराये का मुद्दा उठाए जाने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू से कहा कि वह इसकी जांच कराएं क्योंकि पैसा संसद से जाता है जो चिंता की बात है। नायडू ने कहा कि वह इस शिकायत की जांच कराएंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह की वकालत की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत असम के डिब्रूगढ़ जिले में बंद है।अमृतपाल सिंह के लिए वकालत करते हुए चन्नी ने कहा कि वे हर दिन आपातकाल के बारे में बोलते हैं। लेकिन आज देश में अघोषित आपातकाल के बारे में क्या?

सभापति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि हमारे पास रहने के लिए एक ही ग्रह (पृथ्वी) है और दूसरा ग्रह नहीं है। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान ग्रीन इंडिया मिशन को लेकर पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब के दौरान सभापति धनखड़ ने कहा ''हमारे पास एक ही ग्रह 'पृथ्वी' है और दूसरा ग्रह नहीं है।''

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार किसानों के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है.

झोलाछाप डॉक्टरों पर छापा, मरवाही में प्रशासन ने सील किया क्लिनिक

■ मेडिकल स्टोर भी लपेटे में आया

मरवाही। मरवाही इलाके में बिना अनुमति के अवैध तरीके से संचालित क्लीनिक और मेडिकल स्टोर्स सहित झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को प्रशासन ने सील किया। मरवाही के निमधा और गौरेला के जोगियापारा इलाके में बड़ी कार्रवाई की है।

दरअसल, जिले में लगातार अवैध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति के मेडिकल स्टोर और उसके आड़ में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे है। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन एक्शन में और छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है।

मरवाही के निमधा गांव में बिना अनुमति चल रहे वर्षा जायसवाल क्लीनिक और वर्षा मेडिकल स्टोर्स को नर्सिंग होम एक्ट के तहत तत्काल सील कर दिया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी मरवाही, तहसीलदार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं थाना प्रभारी मरवाही मरवाही की संयुक्त टीम ने तहसील मरवाही के अन्तर्गत ग्राम निमधा में छापेमारी कार्रवाई कर वर्षा जायसवाल के (डिग्री इन योगा एण्ड

हेल्थ) क्लीनिक एवं वर्षा मेडिकल स्टोर को सील किया है।

एसडीएम मरवाही दिलेराम डाहिरे ने बताया कि जांच दल को वर्षा जायसवाल के द्वारा प्रस्तुत क्लीनिक एवं मेडिकल स्टोर से संबंधित दस्तावेज एवं सामग्री की जांच की गई। जांच में पाया गया कि बिना अनुमति के क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। बिना अनुमति के डॉ. रूपेन्द्र मिश्रा क्लीनिक में उपचार कर रहे थे।

वर्षा मेडिकल स्टोर्स, रोहित जायसवाल के नाम से संचालित है। जिसका संचालक वर्षा जायसवाल कर रही। मेडिकल स्टोर में मेडिसिन की बिक्री देवेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जो कि दवाइयों की बिकी हेतु अधिकृत नहीं है, न ही इनके पास कोई वैध डिग्री है, जो पूर्णत: मेडिकल संचालन के खिलाफ पाया गया। मेडिकल स्टोर में रोहित जायसवाल बैठता नहीं है। इस प्रकार वर्षा जायसवाल क्लीनिक एवं वर्षा मेडिकल स्टोर ग्राम निमधा को तत्काल सील किया गया।

वहीं एक अन्य मामले में गौरेला के जोगियापारा इलाके में संचालित झोलाछाप डॉक्टर जुगल किशोर राठौर उर्फ शत्रु राठौर की क्लिनिक को भी सील कर दिया गया है। लगातार अवैध क्लिनिक पर कार्यवाही से जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में अवैध तरीके से डॉक्टरी करने वाले झोलाछाप डॉक्टरो में हड़कंप मचा हुआ है।

झोलाछाप बना यमराज, गलत इलाज से दो बच्चों की मौत

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में एक सप्ताह के भीतर दो अलग-अलग मामलों में दो आदिवासी बच्चों की झोलाछाप डॉक्टरों के गलत इलाज के चलते मौत होने का मामला सामने आया है। जहां पर पहला मामला मरवाही क्षेत्र का है, जिसमें एक 14 साल की स्कूली छात्रा की इलाज का ठेका 1300 रुपये में किया और जब हालात बिगड़ी तो शासकीय अस्पताल भेज दिया। जहां पर उसकी मौत हो गई।

तो दूसरा मामला गौरेला के शासकीय छात्रावास में रहने वाले 12 साल के छात्र की जान का है। उसके गांव के झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज में जान चली गई। फिलहाल, मामले में जिला प्रशासन गम्भीर है। कड़ी कार्यवाही करने की बात कह रहा है।

दरअसल, आदिवासी बाहुल्य जीपीएम जिले में बीते एक सप्ताह के भीतर दो अलग अलग मामलों में दो आदिवासी बच्चों की झोलाछाप डॉक्टरो के गलत इलाज के चलते काल के गाल में समा गए है। पहला मामला मरवाही विकास खण्ड के चिचगोहना के बरझोरखी की रहने वाली 14 साल की छात्रा उमा उरैती से जुड़ा हुआ है। जिसकी तबियत खराब होने पर किसी के द्वारा बतलाया गया कि निमधा गांव में रहने वाला प्रदीप जायसवाल जो कि पेशे से शासकीय शिक्षक है और निमधा के बस स्टैंड में उसकी पत्नी की वर्षा मेडिकल स्टोर भी है। वहां इलाज करता है।

वहीं दूसरा मामला गौरेला के टिकरकला आदिवासी प्री मैट्रिक छात्रावास का है। जहां पर छात्रावास प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। जिसमें एक आदिवासी बच्चे की जान चली गई। दरअसल, कोटमीखुर्द के रहने वाले महिपाल कवर अपने बेटे आयुष कवर को बेहतर शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में स्थित आदिवासी छात्रावास में दाखिला करा दिया। बीती दो जुलाई को उसे छात्रावास में छोड़ आए। पर अचानक 12 जुलाई को हॉस्टल से बच्चे के परिजनों को फोन आया कि आपका बेटा आयुष की तबियत ठीक नहीं है। उसे सर्दी खांसी है।

परिजन बच्चे को लेने 13 जुलाई को हॉस्टल पहुंचे और उसे लेकर बस से अपने गांव कोटमीखुर्द आ गए। जहां से वे सीधे आयुष को लेकर गांव के मुड़ा टिकरा में रहने वाले चन्द्रभान पैकरा जो गांव में झोलाछाप डॉक्टरी करता था। उसके पास ले आए। झोलाछाप डॉक्टर चन्द्रभान ने बच्चे के हाथ में इंजेक्शन लगाया। जिसके बाद बच्चे की तबियत बिगड़ने लगी और झोलाछाप डॉक्टर घबराकर बच्चे को बस्ती गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया।

एनजीओ संचालक कलादास डहरिया के घर छापा

दुर्ग। छग मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के सदस्य कलादास डहरिया से पूछताछ करने एनआईए की टीम आज भिलाई पहुंची। जामुल लेबर कैम्प स्थित कलादास डहरिया के घर एनआईए को टीम पहुंची सीआईएएफ जवान और जामुल पुलिस की टीम भी घर के बाहर तैनात रही। जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई नक्सल गतिविधियों से जुड़े होने के शक जताया जा रहा है। लेकिन एनआईए की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

एनआईए की टीम कलादास की बेटी का लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन जब्त अपने साथ ले गई है। कलादास डहरिया रेला नाम का जनवादी सांस्कृतिक संगठन (ह्लह्ल) चलाते हैं। यह एनजीओ किसान, आदिवासी और मजदूरों के संगठन के लिए काम करता है। इसके लिए इसे देश भर से फंडिंग मिलती है। एनआईए की टीम आज सुबह 5.30 बजे 4-5 गाड़ियों में कलादास डहरिया के घर पहुंचकर छापामारी कार्यवाही की गई।

कार्रवाई को लेकर कलादास डहरिया ने बताया है कि एनआईए ने उनसे नक्सली संपर्क को लेकर सवाल-जवाब किए हैंऔर मेरे मोबाइल में कई लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर हैं। ऐसे में ये नक्सलियों से सांठगांठ की शंका गलत है। हमारे द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ मजदूर और किसानों के हित के लड़ाई लड़ते हैं। जिससे सरकार को बर्दाश्त नहीं और हमारी आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है। वहीं कलादास डहरिया को एक अगस्त को पुछताछ के लिए रांची झारखंड दफ्तर पर उपस्थित होने को कहा है।

100 करोड़ की ठगी का मामला तीनों की जमानत याचिका खारिज

कोरोनाकाल में चलाया था शातिर दिमाग

बिलासपुर। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 100 करोड़ की ठगी करने वाले तीनों आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई है। दरअसल, कोरोना के दौरान नौकरी गंवाने वाले राजनांदगांव जिले के कंपाउंडर सुशील साहू ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने एक डमी एप बनाया।

कंपाउंडर साहू ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसने छत्तीसगढ़ समेत अन्य 8 राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाकर लोगों से करीब 100 करोड़ निवेश करा लिया।

निवेशकों ने जब सुशील साहू से लाभ की रकम मूल समेत लौटाने को कहा तो सुशील उन्हें घुमाने लगा। परेशान निवेशकों ने राजनंदगांव और अन्य थाने में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जमानत के लिए आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इस पर आपत्ति करते हुए अधिवक्ता अंकित सिंह ने जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने पहली सुनवाई में डीजीपी को एसआईटी टीम गठित कर जांच कर शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया था। डीजीपी ने जांच कर शपथपत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

नक्सलियों ने रामाराम सरपंच को चेतावनी के साथ जारी किया फरमान

सुकमा। नक्सलियों के कोण्टा एरिया कमेटी के सचिव मंगडू ने एक के बाद एक दो प्रेस वक्तव्य जारी कर जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के रामाराम ग्राम पंचायत के सरपंच वेट्टी हंदा पर वर्ष 2005 से जनविरोधी काम करने एवे बीमा योजना के नाम से जनता का 3 लाख के ऊपर पैसा बैंक में जमा कर लेने, लोगों का पैसा वापस नही कर 2006 मे जनविरोधी बनकर सलवा जुडूम मे सक्रिय रूप से शामिल होने के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। जो भी वेट्टी हंदा का खिलाफ करेगा उसको पुलिस से गिराफ्तार करवाके जेल भेज देने को धमकी देने का आरोप लगाया है। नक्सनियों ने उपरोक्त सभी आरोपो पर अंतिम चेतावनी जारी करते हुए रिस्तेदारों व परिवार के अलावा किसी समाजिक संगठन से समझाईश देने एवं अपना गलती को स्वीकार करके सुधार करने की चेतावनी के साथ मौत की सजा का फरमान जारी किया है।

नक्सलियों ने 45 परिवारों पर मुखबीरी का आरोप लगाकर दी चेतावनी

सुकमा। नक्सलियों के कोन्टा एरिया कमेटी के सचिव मंगडू ने प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा है कि भेज्जी, कोन्टा, पोलमपल्ली, चिंतागुफा, एर्राबोर थाना क्षेत्र के कुछ गांव के कुछ परिवार सलवा जुडूम के दौरान आंध्रप्रदेश, तेलंगाना राज्य में पलायन कर बस गये थे। अब यहां पुलिस कैम्प थाना खुलने व रोड बनने के बाद वापस लौटकर नक्सली गतिविधि कम होना समझकर पुलिस फोर्स के भरोसे सक्रिय रुप से अपना जनविरोधी कार्य करना, हर एक परिवार से पुलिस फोर्स में भर्ती करवाके नक्सलियों के खिलाफ विरोध एवं पुलिस संपर्क में रहकर मुखबीरी का आरोप लगाया है। इनमे करिगुण्डा, कोर्रापाड़, पिड़मेल, कोलाईगुड़ा, तोलनीय, पेन्टापाड़ के हिड़मा पटेल सहित 45 से ज्यादा परिवार को नक्सलियों के विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अपनी गलती पर क्षमा मांगकर अपने गांव में साधारण रुप से जीवनयपना करने को अपील के साथ चेतावनी दी गई है कि अगर अपनी जनविरोधी कार्य से दूर नहीं होंगे तो उसे सजा दी जायेगी।

फूड प्वाइजनिंग से एक की गई जान पांच की हालत बिगड़ने की खबर

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत दूरस्थ ग्राम खुज्जी में फूड प्वाइजनिंग से एक ही परिवार के पांच सदस्य बीमार हो गए। इनमें 15 वर्षीय बालिका की मौत होने की खबर है। वहीं फूड प्वाइजनिंग से मौत की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य अमले ने गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाया एवं घर-घर पहुंचकर पीड़ितों की जानकारी ले रहे है।

मृतका के परिवार के अन्य सदस्य खतरे के बाहर हैं। जानकारी के अनुसार, उदयपुर से करीब 30 किमी दूर स्थित ग्राम खुज्जी निवासी नारायण मझवार के परिवारजनों ने शनिवार को भाजी की सब्जी बनाई थी। इसे खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य उल्टी-दस्त का शिकार हो गए। मंगलवार को गंभीर रूप से पीड़ित नारायण मझवार की पुत्री फुलमतिया 15 वर्ष की मौत होने की खबर मिल रही है।

वहीं अन्य सदस्यों की हालत भी बिगड़ गई। पंचायत के सचिव व मितानिन की सूचना पर उदयपुर से स्वास्थ्य अमला गांव में पहुंचा एवं पीड़ित नारायण मझवार, उसकी पत्नी बंधई, दो पुत्र आकाश व बैसाखू का उपचार शुरू किया। बुधवार को अंबिकापुर से मेडिकल ऑफिसर

वाईके किंडो की टीम भी खुज्जी पहुंची।

गांव में ही कैंप कर उपचार के बाद चारों पीड़ितों की हालत अब खतरे से बाहर है। स्वास्थ्य अमले ने गांव के अन्य घरों में भी जांच की, लेकिन डायरिया के मरीज नहीं मिले। मौसमी बीमारियों के जो पीड़ित मिले, उन्हें दवाएं दे दी गई हैं। उदयपुर बीएमओ डा. डीएम कामरे ने बताया कि पीड़ित नारायण मझवार के परिवार का उपचार अब भी चल रहा है। उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने में और दो से तीन दिनों का समय लग सकता है। स्वास्थ्य विभाग की पूछताछ में नारायण मझवार ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने भाजी खाई थी। जंगली भाजी की सब्जी के साथ चावल खाया था, जिसके बाद सभी की तबियत बिगड़ी। सभी के उल्टी-दस्त पीड़ित होने के बावजूद तत्काल उनका उपचार नहीं कराया गया। मृतका की एक बहन सुकवारो कस्तूरबा आश्रम उदयपुर में रहती है, जो सुरक्षित है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बिजली से परेशान ग्रामीणों का जेसीबी खड़ी कर चक्काजाम

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के पसान मुख्य मार्ग पर जेसीबी मशीन खड़ी कर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। विद्युत व्यवस्था को लेकर पसान और आसपास के गांव के लोग काफी परेशान हैं। बिजली की समस्या से तंग आकर कटघोरा-पेंड्रा मार्ग के पसान में सड़क पर ग्रामीण बैठ गए हैं। पसान में सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामशरण तंवर के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया है। कई गांव के पंच और सरपंच शामिल हैं। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है।मौके पर पुलिस और तहसीलदार मौजूद हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल को तैना किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बरसात के मौसम में बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं। वहीं घर पर सांप बिछी भी आ रहे हैं। जिससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी हैं।

कोर्ट ने गांजा तस्करों को 18 साल की जेल का आदेश दिया

दुर्ग। जिला विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा और जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 18-18 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यह सजा एनडीपीएस की विशेष न्यायालय को न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आदेश की है। पूरा मामला 20 जुलाई 2023 को कुम्हारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिसा बलांगिर से नागपुर की ओर बड़ी मात्रा में गांजे की खेप ले जाई जा रही है। जिसके बाद एंट्री क्राइम एंड साइबर यूनिट और कुम्हारी थाना पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा के पास घेराबंदी गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की टाटा मांजा कार नंबर सीजी 07 एके 4194 को तलाशी लेने पर डिग्गी में दो प्लास्टिक की बोरी में 50 किलो गांजा जब्त किया था। जिसकी अनुमानित कीमत 17 लाख 80 हजार आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी में गुड्डू यादव राजस्थान और अकलेश लोधी मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।

नक्सल पीड़ित परिजनों को मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति

बीजापुर। नक्सली हिंसा में मृतक के परिजनों को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डेय की अध्यक्षता में इन्द्रावती सभाकक्ष में आयोजित हुई। जिसमें कुल 58 पात्र आवेदकों को प्रथम चरण में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। पूर्व में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 19 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी। जिसे तिथि में पुनर्वृद्धि करते हुए 24 जुलाई 2024 को निर्धारित की गई। उक्त तिथियों में प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण करते हुए समिति के निर्णय के आधार पर विभिन्न विभागों में चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से 58 आवेदक प्रथम चरण में पात्र पाए गए हैं, 2015 के बाद यह नियुक्ति दी जा रही है। 30 जुलाई को आवेदकों की कौसलिंग इन्द्रावती सभाकक्ष में प्रात: 11 बजे आयोजित की जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक जानकारी दी।

अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

कोरिया। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आहूत महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों के अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर अपनी प्रतिउत्तर देने के निर्देश दिए गए है उल्लेखनीय है कि गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, रेषम विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा करते हुए कलेक्टर लंगेह ने उक्त विभागों के अधिकरियों के अनुपस्थिति तथा आधा-अधूरी जानकारी देने पर नाराजगी व्यक्त की तथा इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में रेशम विभाग के सहायक संचालक एस.एन. सिंह, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी बैकुण्ठपुर, बलवंत सिंह, श्रेष्ट मिश्रा के अलावा सीएमओ डॉ. आर.एस. सेंगर, मनोज खलखो, श्रीमती सरस्वती डे तथा सोनहत के शशि जायसवाल को अनुपस्थित तथा संबंधित योजनाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।

धुर नक्सल प्रभावित कुंदेड़ में 4जी मोबाइल सेवा शुरू हुआ

सुकमा। जिले के धुर नक्सल प्रभावित कुंदेड़ में मोबाइल सेवा शुरू हो गई है, यहां जियो कंपनी का 4जी मोबाइल नेटवर्क शुरू कर दिया है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुरक्षा कैंपों के आस-पास नेटवर्क कनेक्टिविटी देने की योजना के तहत यहां टावर लगाया गया है। मोबाइल सेवा शुरू होने के बाद इलाके में एवं वहां तैनात जवानों में खुशी है। टावर से मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का फायदा कुंदेड़ सहित जगरगुंडा, उरसांगल, गोंदपल्ली, दुरनदरभा सहित आस-पास के क्षेत्र को मिलेगा। बीते करीब 1 साल से सुकमा पुलिस ने 14 जगहों पर मोबाइल टावर स्थापित करवाया है। इनमें बाडनपाल, कोत्ताचेरू, पोटकपल्ली, वेलकनगुड़ा, डब्बाकोंटा, टोंडामरका, सुर्रपाल, सिलगेर नाला, जंगमपाल, इडजेपाल, रामाराम, एलारमडगू, - मेखावाया, परिया शामिल हैं।

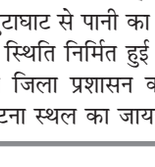

अब नहीं गिरते आँसुओ के बूँद, बहती है यहाँ पानी की धार

नल जल योजना से जल संकट वाले गांवों में दूर होने लगी है पेयजल की समस्या

कोरबा। यह कोरबा जिले के कोरबा विकासखण्ड के अंतर्गत पहाड़ों से घिरा विमलता गाँव है। भले ही इन गांव में रहने वाले परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पानी को लेकर यहाँ की समस्या बहुत बड़ी है। गर्मी क्या आई ? गाँव का हैंडपंप जलस्तर नीचे जाने से जवाब दे जाता था। इस गांव के लोगों ने ऐसे कई गर्मी के मौसम देखे हैं, जो उन्हें पानी के बूँद-बूँद के लिए मोहताज करते हुए उनकी आँखों से आँसुओं के बूँद गिराए हैं। अब जबकि गाँव में जल जीवन मिशन से घर-घर नल लग गया है तो यहाँ पीने के पानी के लिए गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को आँखों से आँसुओं की बूंद नहीं गिराना पड़ता। गाँव में लगे नल और घरों के कनेक्शन से उन्हें गर्मी और बरसात में

स्वच्छ पानी की धार मिल जाती है। उन्हें लगभग एक किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे मुसीबत मोल लेकर खतरनाक ढोढ़ी में पानी भरने नहीं जाना पड़ता।

कोरबा ब्लाक के नकिया पंचायत अंतर्गत ग्राम विमलता में जल जीवन मिशन के माध्यम से नल कनेक्शन घर-घर लगाया गया है। जल संकट वाले इस ग्राम में हर साल गर्मी के दिनों में पानी की समस्या विकराल हो जाती थी। बारिश के समय जान जोखिम में लेकर पहाड़ के चट्टानों के बीच ढोढ़ी का पानी निकालना पड़ता था। इस दौरान पत्थरों के फिसलन होने से गिरने का खतरा भी बना रहता था। वे मटमैला पानी पीने मजबूर थे। ग्राम विमलता की महिला रामवती बाई, फुसुन्दरी बाई ने बताया कि गर्मी आते ही सभी को पानी के लिए जूझना पड़ता है। जलस्तर नीचे चले जाने के बाद समस्या और भी बढ़ जाती थी। बारिश के समय बहुत कम पानी से काम चलाना पड़ता था। अब घर में नल का कनेक्शन लग जाने से सुबह शाम पानी उपलब्ध हो जाता है। उन्हें 01 किलोमीटर दूर ढोढ़ी से पानी नहीं लाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में पानी की समस्या देखकर रोना आ जाता था। ग्रामीण दिलमती बाई ने बताया कि पास का हैण्डपम्प से लगातार पानी निकालने से हैंडपंप भी बिगड़ जाते थे। गांव में सोलर ड्यूल पंप लगा है, जिससे गांव वालों को आसानी से पीने का पानी मिलने लगा है। उन्होंने बताया कि घरों में पेयजल के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं को ही परेशानी उठानी पड़ती थी। उन्हें ही दूर कहीं से पानी लाना पड़ता था। अब ऐसी समस्या दूर हो गई है। गाँव के जनेऊ सिंह का कहना है कि घर-घर नल लगाना बहुत अच्छी पहल है। इससे स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। घरों में नल का कनेक्शन भी लगा है। पानी की सप्लाई से गाँव वालों को राहत मिलने लगी है। सोलर ड्यूल पंप लग जाने से 24 घण्टे पानी की सुविधाएं मिल गई है।

पुल के ऊपर बाढ़ का पानी, वाहनों की लगी लंबी कतार

कोरबा। कोरबा जिले के कटघोरा के धौराभाटा के समीप नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। निरंतर हो रही बरसात के कारण जलस्तर बढ़ा और नदी के ऊपर से पानी बहता देखकर भी एक युवक ने पुल पार करने की कोशिश की। लेकिन वह तेज धार में बहकर निकलने की कोशिश में मारा गया।

कटघोरा बिलासपुर मार्ग बातचीत हो जाने के कारण पुल के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार हुई बारिश के बाद यह स्थिति निर्मित हुई है। जहां नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जहां यात्री बस के अलावा ट्रक , बाइक और कार फंसे हैं और पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं।

यही हाल जिले के पाली विकासखंड के मुंगाडीह गांव की स्थिति रही जहां पानी ने तबाही मचाकर रखी है। हर तरफ लोगों को पानी ही पानी

नजर आ रहा है। पानी के तांडव से कई घर बेघर हो गए हैं। लोगों को जगह खाली करना पड़ा। ग्रामीणों को सामान छोड़कर भागना पड़ा। वहीं कई लोग सामान खाली करने में लगे रहे। इस नजारे को देखने राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने लगे।

बताया जा रहा है कि रतनपुर के जलाशय खुटाघाट से पानी का बहाव नदी में आ गया। जिससे ये स्थिति निर्मित हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। घटना स्थल का जायजा लिया।

संक्षिप्त समाचार

पीएम की अगुवाई में होगी नीति आयोग की बैठक, सीएम साय होंगे शामिल

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में

नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने सीएम साय शुक्रवार शाम को दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। राज्यों के संबंध में नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ाना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। इससे पहले देश में 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जो वर्ष 2014 तक लगातार काम करता रहा। उस समय इसका मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार कर विकास का एजेंडा तैयार करने का था।

सीएम से रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने विधानसभा में की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से

रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने मुलाकात की। राजनांदगांव से आए रॉयल किड्स कॉन्वेंट के कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष श्री चरण दास महंत से भी मुलाकात की। रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने पहली बार विधानसभा की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान जिज्ञासा वश कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने इस अनुभव को अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छात्रों को अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी का राजनीति और सरकारी कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है।

चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने शिवराज भंसाली से मुलाकात कर मुख्य चुनाव अधिकारी पद के लिए मनोनयन पत्र सौंपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड

इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष- राजेन्द्र जग्गी ,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 23 जुलाई 2024 चेम्बर कार्यकारिणी समिति की बैठक में चेम्बर चुनाव-2024 को चुनाव संपन्न करवाने हेतु शिवराज भंसाली को सर्वसम्मति से मुख्य चुनाव अधिकारी मनोनीत किया गया है। अमर पारवानी ने बताया कि चेम्बर चुनाव-2024 को चुनाव संपन्न करवाने हेतु श्री शिवराज भंसाली को मुख्य चुनाव अधिकारी मनोनीत किये जाने पर भंसाली से मुलाकात कर उन्हें मनोनयन पत्र दिया गया। इस अवसर पर चेम्बर सलाहकार मगेलाल मालू, संजय रावत, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुरेश भंसाली, मंत्री-जितेन्द्र गोलछा जैन, जयराम कुकरेजा, प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विस परिसर में लगाया बेल का पौधा

रायपुर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रियों ने विधानसभा आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया।

70 वार्डों की चतुर्दीश सीमा प्रस्तावित कर नया नक्शा जारी

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने अपने 70 वार्डों की चतुर्दीश सीमा प्रस्तावित कर नया नक्शा भी जारी कर दिया है। इस पर दावा आपत्ति आमंत्रित कर उनके निराकरण बाद वार्डों का परिसीमन किया जाएगा।

एडिशनल एसपी निमेश बरैया का निधन, गंभीर बीमारी से थे ग्रसित

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के अधिकारी एडिशनल एसपी निमेश बरैया का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरे पुलिस प्रशासन में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि निमेश बरैया पिछले 3-4 दिनों से राजधानी रायपुर के सुयश अस्पताल में भर्ती थे और गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पहले बलरामपुर एडिशनल एसपी निमेश बरैया को पीलिया हुआ था। उनका इलाज जिले के ही एक अस्पताल में चल रहा था। लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

बालको के विद्युत संयंत्रों, राखड़बांध में पाई गई खामियां : वित्त मंत्री

■ 1429500 रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि किया मंडल मुख्यालय में जमा

रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को बालको के विद्युत संयंत्रों, राखड़बांध एवं फ्लाई ऐश भराव में पाई गई खामियों का मामला प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधानयक धरमलाल कौशिक ने उठाया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि बालको के विद्युत संयंत्रों, राखड़बांध एवं फ्लाई ऐश भराव में पांच खामियां पाई गई हैं और समिति द्वारा उद्योग प्रबंधन के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने / विधिसम्मत कार्यवाही की अनुशंसा की गई जिस पर बालको प्रबंधन ने 1429500 रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मंडल मुख्यालय में जमा किया।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक कौशिक ने वित्त मंत्री से पूछा कि यह सही है कि दिनांक 28.02.2024 को बालको संयंत्र में नियमों का उल्लघंन संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना में माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि मै विभागीय रूप से इस प्रकरण में जांच भी कराऊंगा? यदि हाँ तो किसके द्वारा जांच की जा रही है? समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? जांच के क्या- क्या बिन्दु हैं? समिति की बैठकें कब-कब हुई हैं एवं समिति द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया है? समिति/जांच अधिकारी के द्वारा क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किये गए हैं? जांच में क्या अनियमिताएं पाई गई हैं एवं इसके लिये दोषी कौन हैं तथा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो जांच कब तक पूर्ण हो जावेगी?

वित्त मंत्री चौधरी ने सदन में बताया कि आवास एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के पालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से मेसर्स बालको कोरबा के ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख के भण्डारण, परिवहन एवं अपवहन की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। गठित समिति के सदस्य (1) अनूप कुमार बेहरे अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर, (2) आर. के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर एवं प्रमेन्द्र शेखर पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा है। समिति द्वारा बालको के ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न राख के भण्डारण, परिवहन एवं अपवहन के बिन्दुओं पर जांच की गयी है। उक्त समिति के द्वारा पृथक से बैठक नहीं की गयी है, अपितु मेसर्स बालको के विद्युत संयंत्रों, राखड़बांध एवं फ्लाई ऐश भराव स्थलों का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 एवं 02.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियों पायी गयी:- (1) ऐश संग्रहण सायलो एरिया के आस-पास अत्यधिक मात्रा में ऐश का जमाव होना पाया गया। (2) ऐश डाइक मार्ग पर लगभग 20-30 टन राखड़ के 02 ढेर पाये गये, जिस पर मिट्टी की परत नहीं बिछायी गयी थी। (3) ऐश डाइक के पॉण्ड 02 एवं 06 में पर्याप्त जल छिड़काव व्यवस्था नहीं पायी गयी। (4) निरीक्षण के दौरान 02 वाहनों द्वारा उचित ढंग से तारपोलिन बांधे बिना परिवहन किया जाना पाया गया। (5) ग्राम-बरबसपुर स्थित स्थल पर ऐश के माध्यम से भू-भराव के उपरांत मिट्टी की परत बिछाने का कार्य प्रगति पर होना पाया गया, परन्तु पर्याप्त जल छिड़काव व्यवस्था नहीं पायी गयी, जिसके कारण राख उड़ती हुई पायी गयी।

उपरोक्तानुसार पायी गयी कमियों के संबंध में समिति द्वारा उद्योग प्रबंधन के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने / विधिसम्मत कार्यवाही की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात उद्योग के ताप विद्युत संयंत्र को वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 %क% के तहत नोटिस जारी किया गया एवं पाये गये उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाने बाबत निर्देशित किया गया। उद्योग प्रबंधन के द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने की जानकारी दी गयी एवं कुल 1429500/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मंडल मुख्यालय में जमा किया गया है। उपरोक्त की पुष्टि हेतु दिनांक 10.06.2024 को उद्योग के निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रबंधन द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सोलर स्ट्रीट लाईट खरीद में अनियमितता विधानसभा की कमेटी करेगी जांच

रायपुर। ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट खरीद में अनियमितता का मामला मानसून सत्र के चौथे दिन भाजपा सदस्य सुश्री लता उसेंडी विधानसभा में उठा। इस पूरे मामले पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने न सिर्फ कोंडागांव बल्कि प्रदेश में सोलर स्ट्रीट लाईट खरीदी में गड़बड़ी की जांच विधानसभा की कमेटी से कराने की घोषणा की। प्रश्नकाल में लता उसेंडी ने प्रधानमंत्री आदर्श आवास योजना के मद से सोलर स्ट्रीट लाईट की खरीदी की जानकारी चाही। इस पर आदिम जाति विकास मंत्री नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बल्कि अन्य योजनाओं के मद से सोलर लाईट की खरीदी हुई है। इसमें अनियमितता की कोई शिकायत नहीं मिली है। भाजपा सदस्य ने कहा कि विधानसभा सवाल लगने के बाद आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी गई है कि तीन लोगों ने अनियमितता की शिकायत की थी, और इसकी जांच भी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मर्जी से सोलर लाईट खरीदी की गई। अफसरों ने मर्जी से एजेंसी बदल दी गई, और इसमें गड़बड़ी हुई है। भाजपा सदस्य ने कहा कि यह सब कांग्रेस सरकार में हुआ है। उन्होंने बताया कि ये खरीदी वर्ष-2021-22 में हुई थी। सुश्री उसेंडी ने अनियमितता की विधानसभा की कमेटी से जांच कराने का आग्रह किया।

आदिम जाति विकास मंत्री ने कहा कि न सिर्फ कोंडागांव बल्कि प्रदेश में जहां भी सोलर लाईट खरीदी में अनियमितता हुई है वहां विधानसभा की कमेटी से जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बिन्दु सदन की कमेटी तय करेगी। इसके पूरक सवाल के जवाब में नेताम ने कहा कि राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब बड़ी समिति की घोषणा की गई है, इसलिए राज्य की कमेटी के बिन्दु बड़ी कमेटी में समाहित हो जाएंगे।

गजराज तालाब के आस-पास की भूमि का मामला उठा विस में

रायपुर। गजराज तालाब के आस-पास की भूमि का मामला मानसून सत्र के चौथे दिन भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने विधानसभा में उठाया। जवाब में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने बताया कि रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के आस-पास की भूमि का रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में भू- उपयोग आमोद-प्रमोद प्रयोजन अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान हेतु दर्शाया गया था/प्रस्तावित था तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 अंतर्गत एवं कमल विहार योजना के स्वीकृत लेआउट के अनुसार स्वीकार्य योग्य प्रोजेक्ट विकसित करने का प्लान रखा गया हैं। भूमि के विक्रय हेतु ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 03.02.2023 को आमंत्रित की गई थी। न्यूनतम निविदाकार को आवंटन आदेश दिनांक 12.04.2023 को जारी किया गया था। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदाकार को 05 माह के भीतर प्रथम किश्त की जारी जमा करते हुए अनुबंध निष्पादित किया जाना था, किन्तु निविदाकार द्वारा समयसीमा पर अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया। निविदाकार द्वारा कमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट द्वारा प्रकरण का निपटारा आरबिट्रेशन के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में आरबिट्रेशन की प्रक्रिया जारी हैं।

शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ ही खुलेंगे आर्थिक संभावनाओं के द्वार : साय

■ सीआईआई द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील समिट में हुए शामिल

रायपुर। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन स्टील की ओर रुख कर रही है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, अपितु इस क्षेत्र में नवीन पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में सीआईआई को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है। हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाईयां तो संचालित है ही, इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र के अनेक छोटे-बड़े इस्पात संयंत्र संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दल्लीराजहरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20 प्रतिशत तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने इस्पात उद्योग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के वैश्विक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की सराहना की और राज्य में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई का यह समिट भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज हम इस समिट में ग्रीन स्टील जैसे रोचक विषय पर बात कर रहे हैं। इस शब्द में खूबसूरती तो है ही, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी है।

मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से ग्रीन स्टील उत्पादन की नई तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढने का आह्वान किया और कहा कि हमारी एकजुटता से हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करते हुए मिलजुलकर विकास करेंगे। इस समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने ग्रीन स्टील उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और नई तकनीकों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर सीआईआई के पदाधिकारी और उद्योगपति श्री आशीष सराफ, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, श्री सुवेन्द्र बेहरा, श्री संजय जैन, श्री पी वी किरण अनंत उपस्थित थे।

शारदा चौक-तात्यापारा चौक का चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

रायपुर। रायपुरियंस के लिए राहत भरी खबर है। विधानसभा का मानसून सत्र की व्यवस्ता के बीच भी मुख्यमंत्री जनहित के विषयों पर लगातार मुहर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रायपुर शहर के लिए दो बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक राजेश मूणत, मोतीलाल साहू सहित अन्य विधायक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि रायपुर में शास्त्री चौक के स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। पूर्व अनुमोदित योजना के तहत पूरा निर्माण किया जाएगा। शहर की यातायात सुविधा की दृष्टि से स्काई वॉक बनाया जा

रहा था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद निर्माण रोका गया था।

अब ड्राइंग डिजाइन तैयार कर पूरा निर्माण किया जाएगा। इसी तरह से शारदा चौक तात्यापारा चौक का चौड़ीकरण किया जाएगा। साव ने कहा रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। जो चौड़ीकरण के लिए विस्तार से परीक्षण करेगी कि कितनी जमीन का मुआवजा देना होगा, कितनी जमीन की आवश्यकता होगी। सभी बातों का परीक्षण कर 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर मार्ग का काम बढ़ाया जाएगा। जो अतिरिक्त राशि इस संबंध में लगेगी इसका वहन किया जाएगा। दोनों ही जरूरतें काफी समय से लंबित है। इसके कार्यशील होने के क्षेत्र में बढ़ते कदर शहरवासियों के लिए सुकून भरी खबर है।

70 लाख राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त तक किया जा सकता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख 26 हजार 106 राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है। नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है, कुल हितग्राही 71,329 हितग्राहियों में से 71,109 हितग्राहियों ने, द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला 36,136 हितग्राहियों में से 35,790 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला जहां 78,703 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है।

बूढ़ातालाब परिसर रख-रखाव, नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी रहे बैठक में शामिल

पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों ने दिये विस्तृत दिशा निर्देश

■ नवंबर से पर्यटन मंडल कर रहा है बूढ़ा तालाब परिसर का संचालन एवं संधारण

रायपुर। गत् 17 नवंबर से बूढ़ा तालाब-विवेकानंद सरोवर परिसर के संचालन व रख रखाव की ज़िम्मेदारी निभा रहे पर्यटन बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्य एजेंसी एम.एम.पी. वॉटर स्पोर्ट्स प्रा. लि. की टीम को विस्तृत दिशा निर्देश देने बूढ़ा तालाब परिसर में पर्यटन बोर्ड ने नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्मार्ट सिटी के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री उज्जवल पोरवाल, जीएम (तकनीकी) श्री पी.के. पंचायती, एजीएम इमरान खान, बोर्ड की पर्यटन अधिकारी भावना श्रीवास्तव, एडवेंचर स्पोर्ट्स शाखा के प्रमुख संतोष रैदास, एम.एम.पी. वॉटर के विजय कुमार शामिल रहे।

बैठक में कार्य एजेंसी से कहा गया कि बूढ़ातालाब परियोजना तथा आईलैंड हेतु किए गए 03 उच्चदाब संयोजन संबंधित फर्म एम.एम.पी. वॉटर स्पोर्ट्स अपने नाम पर नामांतरित करेगी तथा अपनी आवश्यकता अनुसार विद्युत संयोजन में अनुबंधित भार कम या ज्यादा कर सकती है। यह फर्म संपूर्ण बूढ़ातालाब परिसर परिक्रमा स्थल में आवश्यक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करेगी तथा वर्तमान में स्थापित सभी अधोसंरचना, उपकरण एवं विद्युत सामग्री का संचालन एवं संधारण उनके द्वारा किया जाएगा। तात्कालिक व्यवस्था अंतर्गत फर्म द्वारा अस्थाई विद्युत मीटर कनेक्शन लेकर कार्यवाही की जाएगी। इस बैठक में फर्म को यह भी निर्देशित किया गया है कि परिसर का व्यवस्थित रख रखाव उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। परिसर में लगे सभी विद्युत व सुरक्षा उपकरण, रोशनी व्यवस्था, नागरिकों की मूलभूत सुरक्षा व्यवस्था के साथ बच्चों के आमोद-प्रमोद के सभी प्रबंध मानक स्तर के साथ संचालित करें। एजेंसी से यह भी कहा गया है कि परिसर की सफ़ाई का पूरा ध्यान रखें और पर्याप्त सफ़ाई कर्मी की तैनाती रखे। समयबद्ध रोस्टर तैयार कर यहाँ लगे उपकरणों की नियमित जाँच करे एवं नागरिक सुझावों पर त्वरित अमल के लिए अपना सिस्टम तैयार करें। ज्ञात हो कि न्यायालयीन आदेश पर रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा बूढ़ा तालाब परिसर के संचालन एवं संधारण का संपूर्ण दायित्व पर्यटन मंडल को 17 नवंबर 2023 को ही स्थानांतरित किया जा चुका है, इसके बाद से यह एजेंसी पर्यटन बोर्ड के मार्गदर्शन इस परिसर का प्रबंधन कर रहा है। इस बैठक में पर्यटन बोर्ड के सहायक अभियंता श्री सतानंद केसरिया, पर्यटन अधिकारी श्री कमलेश सोनवानी, उप अभियंता श्री संदीप दीवान, रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के प्रबंधक श्री संजय अग्रवाल, श्री संदीप शर्मा, असिस्टेंट मैनेजर श्रीमती नेहा पटेल, श्री योगेन्द्र साहू, एम.एम.पी. वॉटर स्पोर्ट्स के श्री शुभम शर्मा, श्री प्रदीप जयदेव भी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 154153/निविदा सूचना क्र. 02/वलेलि/2024-25 कवर्धा, दिनांक 15.07.2024

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनाक 05.08.2024 17:30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम- कबीरधाम जिले के विकासखंड कवर्धा की सरोदा मध्यम जलाशय अंतर्गत अगरी माईगर का रिमाडलिंग, सी.सी लाइनिंग 05 नग व्ही.आर.बी., 03 नग फाल, 02 नग डी.सी., हेड स्लूस एवं नहर विस्तारीकरण कार्य।

अनुमानित लागत रु.- 128.90 लाख

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 22.07.2024 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोट: निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)
जी-242501307/5 अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मण्डल दुर्ग (छ.ग.)

विपक्ष की मुस्लिमों के प्रति अंधश्रद्धा से भाजपा बनी मजबूत

योगेंद्र योगी

मुस्लिम वोटों के लिए विपक्षी नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। विपक्षी दलों को लगना चाहिए कि हितेषी बनने का दिखावा करने मात्र से मुस्लिम वोटों को बटोरा जा सकता है। इसके बाद इन दलों मे आपस में ही सच्चा हितेषी साबित करने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। वोटों की खातिर मुस्लिमों के प्रति इस अंधश्रद्धा का ही परिणाम है कि इसके प्रतिक्रियास्वरूप भाजपा ने न सिर्फ राष्ट्रीय पर संगठन की मजबूत पकड़ बना ली, बल्कि लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में भी आ गई। हालांकि इसमें काफी हद तक केंद्र सरकार के विकास कार्य भी शामिल हैं। मुस्लिमों का हितेषी बनने का नया मामला बांग्लादेश का है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के संकटग्रस्त लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। आश्चर्य की बात यह है कि यह मुद्दा मुख्यमंत्री ममता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। विदेश मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। यह जानते हुए भी ममता ने मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसा बयान दिया। इससे पहले भी ममता बनर्जी सरेआम मुस्लिमों का पक्ष लेती रही हैं। इसके लिए बेशक कानून की मंजूरी हो या नहीं। बर्मा के रोहिंग्या शरणार्थियों का मसला भी केंद्र सरकार के अधीन था। केंद्र सरकार ही तय कर सकती है कि भारत में किसे शरण देनी और किसे नहीं। रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर केंद्र के दृष्टिकोण का विरोध करते हुए ममता ने कहा था कि सभी आम लोग आतंकवादी नहीं हैं और उन्होंने समुदाय का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने की योजना बनाई थी। ममता बनर्जी की शह पाकर कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में रैली निकाली और प्रधानमंत्री मोदी की निर्वासन योजना का विरोध किया तथा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए भारत में आश्रय की मांग की। यह मुद्दा मुस्लिमों के वोट बैंक से जुड़ा हुआ था। इसमें दूसरे विपक्षी दल भी कूद गए। मुस्लिमों के मामले में सभी विपक्षी दलों को लगता है कि कहीं दूसरा दल वोट बैंक का ज्यादा हिस्सा नहीं ले जाए, इसी वजह मुद्दा चाहे राज्यों का हो या फिर केंद्र सरकार से जुड़ा हो, बहती गंगा में हाथ धोने से कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मुस्लिम वोट की खातिर ममता किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इमाम और मुआज्जिम को लेकर बुलाई कॉन्फ्रेंस पर भी राजनीतिक घमासान छिड़ गया था। विरोधी पार्टियों ने इस कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर ममता पर खुलकर तुष्टिकरण और वोट की राजनीति का आरोप लगा दिए। समूचे बंगाल के इमाम और मुआज्जिम इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में कोलकाता पहुंचे थे। गठबंधन की सहभागी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए ममता से मुसलमानों के समग्र विकास के लिए श्वेतपत्र जारी करने की मांग कर दी। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री ममता से सवाल पूछते हुए कहा कि ममता बनर्जी को श्वेत पत्र देकर बताना चाहिए कि वक्फ संपत्ति को बेचकर कितने प्रमोटर करोड़पति हो गए और इनमें से कितने आपकी पार्टी के हैं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में ममता बनर्जी कानून को भी ठेंगा दिखाने में पीछे नहीं रही। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस शासन के तहत 2011 से बंगाल में जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रमाण-पत्रों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। इसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम समुदाय को इस आरक्षण का फायदा मिल रहा था। न्यायालय के इस निर्णय पर ममता बुरी तरह भड़क गई। उच्च न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीशों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने यहां तक कह डाला था कि एक न्यायाधीश कह रहा है मैं आरएसएस का व्यक्ति हूं, दूसरा भाजपा में शामिल हो गया... आप इस तरह से न्यायाधीश कैसे हो सकते हैं और अदालतों की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं ममता सरकार को संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हथियाने व राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में अभियुक्तों को बचाने के लिए पुरजोर पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है।

नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार

अभिनय आकाश

साल 2012 के दिसंबर महीने के बीत है अपना भाषण पूरा नहीं करने दिए जाने से नाराज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक से बाहर निकल जाती हैं। विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक से बाहर निकलते हुए, जयललिता ने केंद्र पर अपने भाषणों को 10 मिनट तक सीमित करके विपक्ष में मुख्यमंत्रियों की आवाज को %दबाने% का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उनका भाषण पूरा करने से रोका जाना उनके लिए %बड़ा अपमान% था। प्रत्येक सीएम को 10 मिनट का समय आवंटित किया गया था और जयललिता को पहले से चेतावनी दी गई थी। जब घंटी बजी तो वह अपने 28 पेज के भाषण के पेज 10 पर थीं। राज्यों और केंद्र के बीच तनातनी का दौर हमेशा से चलता आ रहा है। आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई और विपक्ष की तरफ से नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार जहां बजट को विकसित भारत के निर्माण वाला बजट बता रही है। वहीं विपक्ष ने इसे सरकार बताउ बजट बताकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 27 जुलाई को प्रस्तावित नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में इस बात की आशंका गहराने लगी है कि क्या मानसून सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी या फिर हंगामे में पूरा सत्र यूं ही निकल जाएगा। गौरतलब है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले ही केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। राज्य सरकार ने मेरा कर मेरा अधिकार अभियान चलाया था। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की भावनाओं के अनुरूप राज्य को उचित सहायता नहीं दे रही है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बजट को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। इसके साथ ही ऐलान किया कि नीति आयोग की होने वाली बैठक का कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट के माध्यम से इसकी अवधारणा को नष्ट कर दिया गया है। अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया गया है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होनी है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा एमके स्टालिन और हेमत सोरेन ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। आप शासित राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में नहीं आएंगे।

विपक्ष भले ही बजट को लेकर सवाल उठा रहा है लेकिन उसकी मुहिम को ममता बनर्जी के रुख से तगड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक को लेकर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ की स्थिति भी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अलग राह अपना सकती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी और वो 26 जुलाई को दिल्ली पहुंचेंगी। कहा जा रहा है कि वो पीएम मोदी से मिलेंगी भी और बंगाल के लिए सरकार से फंड जारी करने की मांग भी करेंगे। टीएमसी का तर्क ये है कि वो कांग्रेस के साथ हर मुद्दे पर खड़े नहीं रहेगी। कुछ मुद्दों पर समर्थन है लेकिन इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़कर जीता है। कहीं न कहीं टीएमसी का स्टैंड अलग होगा। ममता कई मुद्दों पर अलग लाइन लेती रही हैं। इंडिया ब्लॉक के साथ रहती हैं कभी अलग राह पकड़ती हैं।

नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था के रूप में की गई थी। इसमें सहकारी संघवाद की भावना से प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा व्यापक विशेषज्ञता वाले लोगों को इसका सदस्य बनाता है। इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। नीति आयोग के पास धन आवंटित करने का भी अधिकार नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) का पुनर्गठन किया है। जिसमें चार पूर्णकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। तथा अर्थशास्त्री सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वैज्ञानिक वीके सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमे चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और मैक्रो अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी भी सरकारी थिंक टैंक के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे।

राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये स्वीकार करते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना तथा इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों पर उत्तरोतर एकीकृत करना। समजा के उस वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पार्यप्त लाभ न मिलने के जोखिम में हैं। प्रमुख हितधारकों एवंम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समानवितचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और सलाह प्रदान करना। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण करना।

प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उनकी अध्यक्षता में हर साल इसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है। केंद्रीय सचिवालय की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार ही काउंसिल की स्थपना की गई है। इसमें सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक सदस्य हैं। अब तक गवर्निंग काउंसिल की आठ बैठकें हो चुकी हैं। इस बैठक में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, विभिन्न सेक्टरों, विभागों से जुड़े विषयों और संघीय मुद्दों पर चर्चा होती है।

नीति आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी बैठक में कोई मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में काम करताहै। ऐसे में विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्रियों की तरफ से इसमें भाग नहीं लेने से इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि वो इसमें अपने राज्य की बात को इस मंच पर नहीं रख पाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में साल 2023 में मई के महीने में बुलाई गई नीति आयोग की बैठक से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाली ममता बनर्जी, जनता दल-यूनाइटेड के बिहार के नीतीश कुमार, भारत राष्ट्र समिति से तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से तमिलनाडु के एमके स्टालिन शामिल थे। राजस्थान के तत्कालिन सीएम अशोक गहलोत और केरल के सीएम पिनारयी विजयन भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अष्टादश-संख्या-विज्ञान (भाग-2)

गतांक से आगे...

सृष्टि का सम्बंध विशेषकर दृश्य आकाश से ही है। उसके 180 अंश हैं। दस- दस का एक विराट् होता है इस नियम से 180 अंश के पुराणाकाश में 18 ही विराट् हैं। बस पुराणाकाश से उक्त ग्रंथों का सम्बंध बताने के लिये भी पुराणों का. 18 होना आवश्यक है।

(5) आदि विद्वान् भगवान कपिल का साँख्यदर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है और पुराणों में सांख्य की प्रक्रिया ही सृष्टि-निरूपण में बहुत अंशों में आहत हुई है- यह पुराणज्ञों से छिपा नहीं है। साँख्य में 25 तत्त्व माने जाते हैं, यथा- मूल प्रकृति 1 प्रकृति विकृति 7. (महान, अहंकार) और पाँच तन्मात्राएं) केवल विकृति 16. (एकादश इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत) और प्रकृतिभाव से अतीत पुरुष 1- यही पच्चीस की गणना है। इनमें मूल प्रकृति और पुरुष की सृष्टि नहीं होती।

यह दोनों अनादि अनन्त तत्त्व है। शेष 23 में पञ्च तन्मात्राओं की ही स्थूल अवस्था पंचमहाभूत है। इन दोनों को एक कर लेने पर सृज्यमान (जिनकी सृष्टि होती है) तत्त्व 18 रह जाते हैं। तब सृष्टि प्रतिपादक ग्रन्थों का अष्टादश संख्या से सम्बन्ध होना तत्त्व-संख्या की दृष्टि से भी उपयुक्त प्रतीत होता है। (7) अध्यात्म दृष्टि से सूक्ष्म शरीर ही व्यावहारिक जीव है इसमें कोई सन्देह नहीं। इस ही में पुण्य पाप का संस्कार रहता है, और इसकी ही लोक परलोक गति होती है। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्त्व सख्यिदर्शन में बताये गये हैं। दश इन्द्रियाँ, मन, पञ्च महाभूतों के सूक्ष्मांश और बुद्धि । यह संसरण काल के सूक्ष्म शरीर का निरूपण है। उस समय अहंभाव नहीं होता, इसलिये अहंकार की गणना इसमें नहीं हुई है। यदि अहंकार वा अहंकारास्पद चिदाभास (जीब) की गणना इसमें और कर ली जाय तो सूक्ष्म शरीर के तत्त्व भी अठारह हो जाते हैं।

क्रमशः ...

कारगिल युद्ध : भारतीय जवानों के बहादुरी, बलिदान व शौर्य की गाथा

अभिनय आकाश

26 जुलाई यह महज एक तारीख नहीं यह दिन है याद दिलाने के लिए कि देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुर्बानी क्या होती है। यह दिन है उन तमाम रणबांकुरे के आगे नमन करने का जो अपने आप को वर्दी में बांधकर देश को सुरक्षित फिजाओं में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यह दिन है उन तमाम साहसी जवानों के आगे झुककर नतमस्तक हो जाने का जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए अग्रसर होते हैं। वह है वतन, देश, हिंदुस्तान हमारा, इंडिया, हमारा भारत...

आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे 21 साल पहले भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम की वह कहानी के बारे में जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बहादुरी की वह मिसाल जो आज भी पाकिस्तान को शूल की तरह चुभती है। 21 साल पहले पाकिस्तान के छल और धोखे के जवाब में भारत ने उसे ऐसा घाव दिया था जिसकी टीस आज भी उसके जेहन में जिंदा है। 21 साल पहले साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में हुई लड़ाई की कहानी भारतीय सैन्य इतिहास का वह महान पन्ना जहां भारतीय जवानों ने असंभव को संभव कर के दिखा दिया था।

14 मई 1999 को भारतीय सेना के कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तानी घुसपैठियों की मौजूदगी के बाबत खबर मिलने के बाद अपनी टुकड़ी को लेकर पेट्रोलिंग पर निकल गए। कैप्टन सौरभ कालिया जल्द ही अपने साथियों के साथ उस ठिकाने तक पहुंच गए, जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठिए मौजूद थे। यहां पर कैप्टर सौरभ कालिया और उनके साथियों की संख्या महज पांच थी, जबकि घात लगाए बैठे दुश्मनों की संख्या सैकड़ो में थे। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उसके साथियों का अपहरण कर लिया। जिसके बाद उनकी और उनके साथियों की निमृम तरीके से हत्या कर दी गई। 25 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान देश को कारगिल में हुई घुसपैठ की जानकारी दी। वहीं 26 मई को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एवाई टिपनिस ने एयर स्ट्राइक के आदेश जारी कर दिए। भारतीय वायुसेना के जवानों की ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। इस बमबारी ने पूरे कारगिल को थर्रा दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों को ये एहसास करा दिया कि वो भले ही ऊंचाई पर बैठे हो, लेकिन वायुसेना के गोलों से दूर नहीं। वायुसेना को ये जिम्मेदारी कारगिल में घुसपैठियों को भगाने और थल सेना की मदद के लिए सौंपी गई थी। 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने मिग 27 विमान से द्रास की चोटियों की तरफ रवाना हुए और 11 जुलाई को भारतीय सेना के खौफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को भागते हुए देखा गया। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा कर दी। 26 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का एलान किया।

ब्रिटेन में लीड्स क्यों सुलग उठा

बलबीर पुंज

बीते दिनों ब्रिटेन के लीड्स स्थित हेयरहिल्स उपनगर में जो कुछ हुआ, वह क्यों हुआ और उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं? इसके 2 पहलू हैं, जिस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि 18 जुलाई को हेयर हिल्स क्यों सुलग उठा? इस क्षेत्र की लक्सर स्ट्रीट में 'बाल कल्याण संस्था' के कर्मचारियों द्वारा बच्चों को उनके परिवार से अलग करने और जबरन 'चाइल्ड केयर होम' में रखने के बाद उपद्रव शुरू हुआ था। परिवार के 4 बच्चों में से एक की पिटाई का वीडियो किसी पड़ोसी ने शहर की बाल कल्याण एजेंसी को भेज दिया था। पूरा मामला हेयर हिल्स के खानाबदोश रोमा (जिप्सी) समुदाय से जुड़ा था, जिनके लोगों ने पहले झगड़ा शुरू किया। परंतु बाद में पुलिस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए पाकिस्तानी-बंगलादेशी मूल के मुसलमान भी इसमें कूद पड़े और देखते ही देखते क्षेत्र में अराजकता फैल गई। दंगाइयों ने जगह-जगह आगजनी करते हुए डबल-डैकर बस को फूंक दिया, निजी-सार्वजनिक संपत्ति पर पत्थर बरसाए और पुलिस अधिकारियों पर हमला बोलकर उनके वाहनों को पलट दिया।

इस संबंध में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं। हेयरहिल्स की आबादी करीब 31 हजार है, जिसमें 42 प्रतिशत हिस्सेदारी मुसलमानों की है, तो ईसाई जनसंख्या 37 प्रतिशत है। दरअसल, लीड्स दंगा अपने भीतर 2 समस्याओं को समेटे हुए है। इसमें पहला संकट पश्चिमी और पूर्वी दुनिया के बीच सांस्कृतिक भिन्नता से जुड़ा है। किसी भी देश के नियम-कानूनों में उसकी संस्कृति की झलक दिखती है। अमरीका और यूरोपीय देश पूर्वाग्रह-गफलत के शिकार हैं कि उनकी संस्कृति-परंपरा, जीवनशैली और तौर-तरीके ही बाकी दुनिया के लिए आदर्श हैं। जबकि सच्चाई क्या है, यह अमरीका में 13 करोड़ वयस्कों के अकेलेपन का शिकार होने, अभिभावक-बच्चे एक-दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करने, अधिक तलाक दर होने और अमरीकी सरकार द्वारा अपने कुल बजट का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल पर खर्च करने की मजबूरी से स्पष्ट है। इसकी तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में पारिवारिक-सामाजिक मूल्य अब भी बहुत मजबूत है, जिसे तोडने के कुटिल प्रयास दशकों से किए जा रहे हैं।

ब्रिटेन के साथ जर्मनी, नॉर्वे सहित कई पश्चिमी देशों में बच्चों के पालन-पोषण को लेकर सख्त नियम हैं। बाल-कल्याण से जुड़ी संस्थाएं ऐसे परिवारों की तलाश में रहती हैं, जिनके बच्चों को लेकर 'चाइल्ड प्रोटैक्शन' से जुड़े नियमों के तहत कार्रवाई हो सके। इनमें अभिभावकों द्वारा बच्चे को थप्पड़ मारना या उनके सामने हिंसा करना ही नहीं, बल्कि उन्हें डांटना, हाथ से खाना खिलाना और यहां तक कि उन्हें अपने साथ एक ही बिस्तर पर सुलाना तक भी अपराध की श्रेणी में आता है।

इस प्रक्रिया में सुरक्षा का हवाला देकर 'वैल्फेयर कोर्ट' बच्चे को उसके मां-बाप से अलग करके स्थानीय परिवारों को सौंप देते हैं, जिन्हें 'फोस्टर पैरेंट्स' कहा जाता है और कुछ देशों में इन्हें दूसरों के बच्चे संभालने के बदले मोटी रकम दी जाती है।

प्रवासी भारतीयों से जुड़े ऐसे ढेरों उदाहरणों में से एक चर्चित मामला जर्मनी से भी सामने आया था। इसमें 23 सितंबर 2021 को 7 महीने की अरिहा शाह को उसके माता-पिता से तब अलग कर दिया गया था, जब वे अपनी बेटी को 'आकस्मिक चोट' का उपचार कराने अस्पताल ले गए थे। तब चिकित्सक ने 'चाइल्ड केयर सर्विस' को फोन करके बुलाया और बच्ची को उन्हें सौंप दिया। अरिहा अब 3 वर्ष से अधिक की हो गई है और अब भी जर्मनी के युवा कल्याण कार्यालय (जुगेंडमट) के संरक्षण में है। उसकी वापसी हेतु अरिहा का परिवार भारत सरकार के समर्थन से न्यायिक और कूटनीतिक मार्ग अपना रहा है। इस पृष्ठभूमि में हेयरहिल्स में बाल कल्याण एजैंसी के खिलाफ खानाबदोश रोमा समुदाय और उनके समर्थन में पाकिस्तानी-बंगलादेशी मुस्लिमों द्वारा मचाया उत्पात क्या दर्शाता है? अक्सर, मुस्लिम समाज का एक वर्ग, विशेषकर उस देश में जहां वे अल्पसंख्यक होते हैं, किसी भी मामले में असहमति या विरोध जताने के लिए हिंसा का सहारा लेता है।

लीड्स घटनाक्रम से 2 साल पहले ब्रिटेन के लेस्टर-बर्मिंघम में भी हिंदुओं को चिन्हित करके उनके घरों-मंदिरों पर योजनाबद्ध हमला हुआ था। स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी आदि यूरोपीय देश भी हालिया वर्षों में इसी प्रकार के मजहबी दंगों का शिकार हो चुके हैं। यह दिलचस्प है कि जो राष्ट्र घोषित रूप से इस्लामी है या शरीया द्वारा संचालित है, वहां भी मुसलमानों का अपने सह-बंधुओं के साथ मजहब के नाम पर ड्क्षहसक टकराव है। यूरोप में अधिकांश मुसलमान प्रवासी मूल के हैं, जिनका संबंध उन्हीं गृहयुद्ध से जूझते या युद्धग्रस्त मध्यपूर्वी इस्लामी देशों से है। इस संकट की बड़ी वजह एकेश्वरवादी मुस्लिम समाज में प्रचलित मध्ययुगीन अवधारणा (काफिर-कुफ्र-शिर्क सहित) और सर्वमान्य जीवनमूल्यों (सह-अस्तित्व सहित) के बीच टकराव है। किसी भी सभ्य समाज में असहमति का स्थान होता है, ड्क्षहसा का नहीं। इसलिए तमाम पूजा-पद्धतियों को चाहिए कि वे अपनी सड़ी-गली अवधारणाओं को परिमार्जित करके उसे शाश्वत सह-अस्तित्व की भावना से युक्त बनाए।

आज का इतिहास

1953 कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में सफल क्रांति की शुरुआत हुई।
1956 मिस्त्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया।
1965 मालदीव ब्रिटेन के अधीनता से स्वतंत्र हुआ।
1990 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने अमेरिकन्स डिसएबिलिटीज एक्ट, एक व्यापक नागरिक अधिकार कानून में हस्ताक्षर किए, जो कुछ परिस्थितियों में, विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।
1992 मैन ऑफ ला मंच 108 प्रदर्शनों के बाद मारकिस थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में बंद हो गया।
1998 एटीएंडटी और ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी पीएलसी ने संयुक्त उपक्रम बनाने की घोषणा की।
2005 कोलंबिया की आपदा के बाद शटल डिस्कवरी एसटीएस - 111 की पहली उड़ान।
2005 नासा के अंतरिक्ष यान डिस्कवरी का प्रक्षेपण किया।
2007 पूरे वेल्स में व्यापक विवाद के बाद, शाम्बो, एक ब्लैकफ्रीशियन बैल जिसे स्थानीय हिंदू समुदाय द्वारा अपनाया गया था, गोजातीय गोजातीय तपेदिक के बारे में चिंताओं के कारण मारा गया था।
2007 पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति सम्पन्न क्रूज मिसाइल बाबर हत्फ़-7 का सफल परीक्षण किया।
2008 यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक और नये ग्रह की खोज की।
2009 आतंकवादी इस्लामवादी संप्रदाय बोको हरम ने नाइजीरिया पुलिस बल स्टेशन पर हमला किया, जिसमें कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी, नाइजीरिया में 1,000 से अधिक लोग मारे गए।
2010 अफगानिस्तान में युद्ध से संबंधित घटनाओं का विवरण देने वाले 92,000 से अधिक वर्गीकृत दस्तावेज़ विकिलिक्स द्वारा जारी किए गए हैं; यह अमेरिकी सैन्य इतिहास में सबसे बड़ा रिसाव है।
2011 वियतनाम ने प्रधान मंत्री गुयेन टैन डंग को फिर से चुना।
2012 ट्रॉपिकल स्टॉर्म खानुन ने दक्षिण कोरिया में 16,000 लोगों को बेघर कर दिया।
2012 सीरिया में हुई हिंसा में एक दिन में करीब 200 लोग मारे गए।
2013 पाकिस्तान के पराचिनार में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 57 मारे गए।

रोजगार के नए अवसर और आर्थिक विकास को गति देगा आम बजट

प्रह्लाद सबनानी

हाल ही में लोकसभा के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुन: सौंपी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भारतीय संसद में पेश किया है। इस बजट के माध्यम से भारत की आर्थिक विकास दर को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करना एवं उनके कौशल को विकसित करना, गरीब नागरिकों को भी विकास में हिस्सेदारी देना एवं उन्हें सामाजिक न्याय देना, विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्रों को विकसित करना, ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आधारभूत ढांचा विकसित करना, नवाचार, शोध एवं विकास करना तथा नई पीढ़ी के सुधार कार्यक्रमों को लागू करना।

केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत खर्चों में लगातार की जा रही वृद्धि के चलते भारत की आर्थिक विकास दर को पंख लगते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसमें 33 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया था। अब वित्तीय वर्ष 2024-45 के लिए इसे और आगे बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में न केवल स्थिरता दिखाई देने लगी है बल्कि यह लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है। आज पूरे विश्व में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रही है।

बजट का गहराई से अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि केंद्र सरकार ने अब भारत में रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने की ठान ली है। भारत के युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं कौशल विकसित करने की दृष्टि से 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाओं के एक पैकेज की घोषणा की है। शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की राशि इस बजट में आबंटित भी कर दी गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत श्क्क्न्ह के प्रथम बार सदस्य बनने पर औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के श्क्क्न्ह खातों में एक माह का वेतन जमा किया जाएगा। इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत एक माह का वेतन (15000 रुपए की अधिकतम राशि तक) तीन किस्तों में उनके खातों में जमा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक माह में एक लाख रुपए तक का वेतन पाने वाली कर्मचारी ही पात्र होंगे। इससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होने की सम्भावना बजट में व्यक्त की गई है।

ऐसे भी कई निर्णय लिए जा रहे हैं जिनसे आने वाले समय में धरातल पर युवाओं को लाभ होता दिखाई देगा। एक करोड़ युवाओं को आगामी 5 वर्षों के दौरान इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत काम दिया जाएगा। ताकि ये युवा वर्ग के नागरिक रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम हो सकें। इन युवाओं को प्रति माह 6,000 रुपए तक का वाजीफा सम्बंधित कम्पनियों द्वारा अदा किया जाएगा। वजीफे की इस राशि को कम्पनियों के लिए लागू निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत किया गया खर्च माना जाएगा। भारत की सबसे बड़ी 500 कम्पनियों को इस योजना के अंतर्गत युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा देनी होगी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा भी इन युवाओं को प्रतिमाह 5000 रुपए अदा किए जाएंगे। यह केंद्र सरकार का एक सूझबूझ भरा निर्णय कहा जा सकता हैं। साथ ही, विनिर्माण के क्षेत्र के रोजगार के नए अवसर निर्मित करने की पहल भी की जा रही है। नए कर्मचारियों के श्क्क्न्ह खाते में जमा होने वाली राशि को आगामी 4 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इससे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों को ही लाभ होगा। इस योजना का लाभ 30 लाख युवाओं को होने जा रहा है। एक अन्य योजना के अंतर्गत नियोक्ता को अपने नए कर्मचारियों के श्क्क्न्ह खातों में जमा की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति आगामी 2 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इससे रोजगार के 50 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के समय में भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक पर्यटन को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन से देश में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब वर्ग की आय में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। श्री विष्णुपाद मंदिर कोरिडोर, गया, बिहार एवं श्री महाबोधि मंदिर कोरिडोर बोधगया, बिहार को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार देश में अन्य मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है ताकि देश में इन मंदिरों में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो तथा भारत को वैश्विक पटल पर एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में दिखाया जा सके।

भारत के ग्रामों में निवास कर रहे नागरिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन करते हैं। अत: ग्रामों में ही रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की मद पर 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह सुविधा तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त ऋण के व्यवसाईयों को प्राप्त होगी एवं जिन्होंने पूर्व में लिए गए 10 लाख रुपए के ऋण की राशि को समय पर अदा कर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भी ऋण की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक करोड़ आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन एक करोड़ आवासों पर 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा, इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 2.2 लाख करोड़ रुपए की रहेगी। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 करोड़ आवासों का निर्माण करने की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी है।

देश के आर्थिक चक्र को गति देने के उद्देश्य से नई कर प्रणाली के अंतर्गत वेतनभोगी/पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए सामान्य छूट की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही, आय कर की दरों में कुछ इस प्रकार का संशोधन किया गया है कि 15 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 17,500 रुपए का लाभ होगा। इस निर्णय से मध्यम वर्गीय नागरिकों के हाथों में कुछ अधिक राशि बचेगी और इस राशि इस इनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था के चक्र में मजबूती आएगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कुल आय का अनुमान रुपए 31.07 लाख करोड़ रुपए का लगाया गया है, इसमें ऋण की राशि शामिल नहीं है परंतु, करों के मद से प्राप्त होने वाली 25.83 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। जबकि, कुल खर्च का अनुमान 48.21 लाख करोड़ रुपए का लगाया गया है।

अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि होने के साथ देश बनेगा महाशक्ति

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम सम्पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। उनकी ओर से प्रस्तुत यह बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए आगे की राह दिखाने वाला है। इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, नौकरीपेशा को थोड़ी राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी उन्नयन, क्षमता विस्तार, हरित एवं कृषि विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी के नए भारत-सशक्त भारत-विकसित पर बल दिया गया है। सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद इस बजट के प्रावधान देश को स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार बजट ने अर्थव्यवस्था में नई परम्परा के साथ राहत की सांसें दी हैं तो नया-भारत, सशक्त-भारत, विकसित-भारत के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलों का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ किसानों, आदिवासियों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक-कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है।

पांच साल के लिए मजबूत नींव रखता बजट

टी वी मोहनदास पाई

वर्ष 2024 का बजट अत्यधिक प्रत्याशित रहा, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद कि पिछला दशक आने वाले पांच वर्षों में अपेक्षित परिवर्तनकारी परिवर्तनों के लिए केवल एक प्रस्तावना या ट्रेलर था। यह बजट नौ प्रमुख क्षेत्रों के आसपास संरचित है, जिसमें रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है, जो सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए अच्छी भुगतान वाली नौकरियां निर्मित करने की अपनी प्राथमिकता में काफी स्पष्ट रही है। इस संबंध में, शिक्षा के लिए बढ़ा हुआ बजट आवंटन दूरगामी प्रभाव वाला एक रणनीतिक कदम है। दूसरी तरफ, कृषि अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य दूरगामी सोच वाले दृष्टिकोण को दर्शाते हुए उत्पादकता बढ़ाना है।

एक और उल्लेखनीय पहल रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन कार्यक्रम है, जहां सरकार भविष्य निधि में नियोक्ता का हिस्सा और ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नए कर्मचारियों के लिए पहले महीने का वेतन, जो पंद्रह हजार रुपये तक हो, कवर करेगी। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। कार्यबल में महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ बजट आवंटन और शिक्षा ऋण की ब्याज दरों में तीन प्रतिशत की छूट समावेशी विकास की दिशा में सराहनीय कदम हैं। इसके अलावा, सरकार ने एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है जिसका लक्ष्य एक करोड़ भारतीय युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में आवासीय और व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना है, ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को कम किया जा सके। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राजनीति में विश्वस्त सहयोगी होने के नाते स्वाभाविक भी था। बिहार के लिए, कोसी नदी बेसिन में बाढ़ सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बजट क्रेडिट गारंटी योजना को बढ़ाना और मुद्रा लोन सीमा को रुपये 20 लाख तक बढ़ाने जैसे उपायों से एमएसएमई को आवश्यक वित्तीय सहायता मिलने, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बजट में शहरी विकास को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है, जिसमें जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं परिवहन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कई सुधारों के प्रस्ताव के साथ सरकार ने शहरी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो सतत विकास एवं जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत का भविष्य शहरी क्षेत्रों पर ही निर्भर है। बजट में ऊर्जा परिवर्तन को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिसमें सोलर रूफटॉप नीति की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की फंडिंग के लिए एक लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो नवाचार के महत्व को रेखांकित करता है। बजट में रोजगार, भूमि संबंधी मामलों और वित्तीय क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा पेश की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना है। बजट प्राप्तियां बढ़कर 32.07 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं, जबकि राजकोषीय घाटा जो अंतरिम बजट में 5.1 फीसदी था, वह घटकर 4.9 फीसदी रह गया है। यह कमी मुख्य रूप से जीडीपी में वृद्धि, उच्च प्राप्तियों और कम व्यय के कारण आई है।

2023-24 के वास्तविक खातों से पता चलता है कि संशोधित बजट में निर्धारित 5.8 फीसदी की तुलना में राजकोषीय घाटा घटकर 5.6 फीसदी रह गया है। बजट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में कई तरह के बदलाव लाता है। हालांकि अप्रत्यक्ष करों, विशेष रूप से जीएसटी का सरलीकरण एक सकारात्मक कदम है। लेकिन कर कटौती एवं उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी जैसे कई मुद्दे अब भी हैं। कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी से शेयरबाजार में सूचीबद्ध निवेशकों के लिए चिंताएं बढ़ी हैं। सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है, जबकि शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध, दोनों प्रतिभूतियों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को एक समान 12.50 फीसदी रखकर दोनों के बीच के अंतर को पाट दिया है। यह गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए दर में बड़ी कमी है, जिससे स्टार्ट-अप्स में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। सोना एवं चांदी पर कर घटाकर छह फीसदी कर दिए जाने से इनकी तस्करी तो घटेगी ही, मूल्यवर्धन एवं निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एंजल टैक्स हटाने से स्टार्ट-अप को भी बड़ी राहत मिली है। व्यक्तिगत कराधान के मामले में बजट ने कई लोगों को निराश किया है। जबकि प्रति व्यक्ति 17,500 रुपये की सकल कटौती के साथ कुछ कर राहत दी गई है। कर संरचना के छह स्लैब को बनाए रखना शायद अनावश्यक रूप से जटिल है। तीन-स्लैब की संरचना अधिक सरल होती।

बजट का एक और महत्वपूर्ण पहलू विवाद समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत का उद्देश्य कुछ लंबित आयकर विवादों को हल करना है। प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन यह अधिक प्रभावी होता, यदि उच्च न्यायालय के निर्णयों का बेहतर सम्मान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए सीमा कम से कम 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी जाती। कुल मिलाकर, यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आगामी पांच साल के लिए ठोस नींव रखता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में राहत और प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें रोजगार सृजन, शहरी विकास और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

घोषणाओं में दिखा वित्त मंत्री का राजकोषीय विवेक

ए के भट्टाचार्य

नरेंद्र मोदी सरकार के अपने छठे पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दिखाया कि वह राजकोषीय विवेक, साहस और राजनीतिक समझदारी सब रखती हैं। उनका राजकोषीय विवेक न केवल 2024-25 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कम करके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 फीसदी तक लाने में नजर आता है बल्कि उनकी इस घोषणा में भी दिखता है कि वह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 2026-27 से केंद्र सरकार के घाटे में कमी के साथ तालमेल वाला बनाएंगी।

वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे के लिए 5.1 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था जिसका मतलब था कि सरकारी ऋण जीडीपी का 57.2 फीसदी होगा। मंगलवार को पेश बजट में घाटे के लिए 4.9 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया जो सरकारी ऋण को कम करके जीडीपी के 56.8 फीसदी के स्तर पर लाएगा। यकीनन कर्ज का यह स्तर अभी भी आधिकारिक समिति द्वारा कुछ माह पहले तय किए गए 40 फीसदी के लक्ष्य से अधिक है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगलवार तक कोविड के बाद के अपने सभी बजट भाषणों में यह लक्ष्य रखा गया कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाना है लेकिन सरकारी ऋण के स्तर में कमी का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को इस गति से कम करने का जिक्र किया जिससे कि सरकारी ऋण के स्तर में भी कमी आए। उन्होंने कहा, '2026-27 के बाद से हमारा प्रयास होगा कि राजकोषीय घाटे को ऐसा रखा जाए ताकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी केंद्र सरकार का ऋण गिरावट पर हो।' यह एक स्वागतयोग्य और

जरूरी बात है जिस पर सरकार की राजकोषीय मजबूती की रणनीति के तहत ध्यान देना आवश्यक था। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की अलग तरह की दिक्कतों को देखते हुए कर्ज के स्तर को राजकोषीय मजबूती के अधिक विश्वसनीय आधार के रूप में देखा जा रहा है।

सीतारमण के वित्तीय विवेक को एक और तरह से आंका जा सकता है। उन्होंने रिजर्व बैंक से अतिरिक्त लाभांश मिलने के बावजूद खुद को विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन करने से रोके रखा। यह लाभांश जीडीपी के 0.4 फीसदी के बराबर है। उन्होंने इस बात को सही चिह्नित किया कि यह इस वर्ष हुआ एकबारगी लाभ हो सकता है और अगले वर्ष शायद अतिरिक्त लाभांश मौजूद नहीं हो। ऐसे में इस वर्ष अतिरिक्त धनराशि होने के बावजूद उन्होंने राजस्व आवंटन को केवल छह फीसदी बढ़ने दिया। बिना ब्याज भुगतान के वास्तविक इजाफा 4.78 फीसदी रहा यानी लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने पूंजीगत व्यय में 17 फीसदी इजाफा बरकरार रखा है। ऐसे में केंद्र सरकार का कुल व्यय 8.5 फीसदी बढ़ने वाला है जबकि उसका कुल राजस्व 15 फीसदी बढ़ेगा। आखिर में सीतारमण ने अपने व्यय की गुणवत्ता और मिश्रण में भी सुधार किया। इतना ही नहीं उन्होंने राजस्व घाटे को भी निरंतर कम किया। 2022-23 के जीडीपी के 4 फीसदी के मुकाबले राजस्व घाटा 2023-24 में 2.6 फीसदी रह गया और अब उसके लिए 1.8 फीसदी का लक्ष्य है। राजस्व घाटे में कमी के साथ ही सरकार के पास यह गुंजाइश होगी कि वह पूंजीगत व्यय में उधारी का अधिक हिस्सा डाले।

वित्त मंत्री इसलिए भी साहसी हैं क्योंकि उन्होंने हर प्रकार की परिसंपत्तियों से हासिल पूंजीगत लाभ पर कर का पुनर्गठन किया है। इसका परिणाम अल्पावधि और दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ कर में इजाफे के रूप में सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प कारोबार पर लगने वाले प्रतिभूति विनिमय कर (एसटीटी) में भी इजाफा किया है। याद रहे कि बजट के पहले आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था के जरूरत से अधिक वित्तीयकरण के जोखिम को रेखांकित किया गया था। शेयर बाजार में वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में तेज वृद्धि इसमें शामिल है। समीक्षा में कर नीतियों और पूंजी और श्रम आय के साथ उसके व्यवहार के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया है।

ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ कर और एसटीटी को लेकर जो घोषणाएं की हैं वे दरअसल समीक्षा में जताई चिंताओं की बदौलत हैं। परंतु जब बात सालाना बजट तैयार करने की आती है तो शेयर मार्केट के मामले में वित्त मंत्रियों को जोखिम से बचने के लिए जाना जाता है। कुछ ही वित्त मंत्री शेयर बाजार को निराश करने वाली घोषणा करते हैं। सीतारमण ने यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया। आश्चर्य नहीं कि घरेलू स्टॉक एक्सचेंज के मानक सूचकांकों में मंगलवार को तेजी से गिरावट आई लेकिन बाद में उनमें सुधार देखने को मिला। वित्त मंत्री की राजनीतिक समझदारी तब नजर आई जब उन्होंने रोजगार से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक के बाद एक कई घोषणाएं कीं।

केंद्रीय बजट में चुनावी राज्यों का नजरअंदाज

के.एस. तोमर

केंद्रीय बजट अनुमानों में 2024-25 के लिए भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण का चरम प्रमाण देखने को मिला। बिहार को बाढ़ शमन के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आबंटन है जिसे लोकसभा में अपनी कम होती ताकत के बाद भाजपा को सरकार बनाने में मदद करने के लिए पुरस्कार के रूप में इसकी व्याख्या की जा रही है। जबकि हिमाचल और उत्तराखंड को जुलाई/अगस्त, 2023 में अभूतपूर्व तबाही का सामना करना पड़ा था, जिसमें क्रमश: 12,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान हुआ था, लेकिन बजट में इन आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। बिहार को बजट में प्रमुखता मिली, लेकिन हिमाचल और पंजाब को नजरअंदाज किया गया। हिमाचल सरकार असमंजस में है क्योंकि 550 लोगों की जान चली गई और लाखों असहाय लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्री से उदार विशेष पैकेज की उम्मीद थी, जिन्होंने राज्य को केवल वित्तीय सहायता के बारे में आश्वासन देना पसंद किया, लेकिन बजट का कोई आबंटन नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब को भी छोड़ दिया, जिसने 23 जिलों में से 21 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण तबाही देखी और 1,680 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान झेला। लगभग 70 लोगों की जान चली गई और राज्य सरकार वित्तीय सहायता की मांग कर रही है, जिसे इस बजट में नजरअंदाज कर दिया गया है। आलोचक योजना कार्यान्वयन में अक्षमताओं को भेदभाव के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। 2024-25 के बजट में, जल जीवन मिशन (70,000 करोड़ रुपए) और कौशल विकास (25,000 करोड़ रुपए) के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आबंटित की गई है। विपक्षी शासित राज्यों ने इन योजनाओं में देरी और अपर्याप्त क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताई है। राज्यों के साथ भेदभाव = 2024-25 के केंद्रीय बजट में फंड आबंटन और वित्तीय सहायता के मामले में राज्यों के साथ भेदभाव को लेकर चिंता जताई है। इन चिंताओं को उजागर करने वाले आंकड़ों के विवरण इस प्रकार हैं -पहला, राज्यों को धन का हस्तांतरण है। 2023-24 आबंटन 8.15 लाख करोड़ रुपए रहा। 2024-25 आबंटन 8.50 लाख करोड़ रुपए है। मुद्दा यह है कि हालांकि राज्यों को धन के हस्तांतरण में वृद्धि हुई है, लेकिन विकास दर राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली बढ़ती मांगों और राजकोषीय दबावों के अनुरूप नहीं है। दूसरा, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान। 2023-24 आबंटन 1.50 लाख करोड़ रुपए रहा। मुद्दा यह है कि स्थानीय निकायों के लिए अनुदान में मामूली वृद्धि स्थानीय सरकारों की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए अपर्याप्त है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जिन्हें बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। तीसरा, राज्य-विशिष्ट अनुदान। 2023-24 में आबंटन 1.20 लाख करोड़ रुपए रहा जो 2024-25 में आबंटन1.18 लाख करोड़ रुपए हुआ। मुद्दा यह रहा कि राज्य-विशिष्ट अनुदानों में मामूली कमी आई है, जो विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं और विकासात्मक परियोजनाओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह कमी राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। चौथा, क्षेत्रीय आबंटन और केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सी.एस.एस.) ग्रामीण विकास 2023-24 में1.55 लाख करोड़ रुपए रहा जोकि 2024-25 में 1.52 लाख करोड़ रुपए हुआ। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ग्रामीण और शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए आबंटन में कटौती से राज्यों की बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, आवास और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने की क्षमता प्रभावित होती है। पांचवां, स्वास्थ्य और शिक्षा अनुदान। स्वास्थ्य क्षेत्र में आबंटन 2023-24 में 80,000 करोड़ रुपए रहा। 2024-25 में 82,000 करोड़ रुपए हो गया। मुद्दा यह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मामूली वृद्धि के बावजूद, बढ़ती जरूरतों को देखते हुए समग्र आबंटन अपर्याप्त है। संबंधित घटनाक्रम में, वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे चुनाव वाले राज्यों को पूरी तरह से छोड़ दिया। हालांकि उनमें से 2 भाजपा शासित हैं।

देवभूमि के लोकप्रिय नाम से ज्ञात हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित उत्तरी भारत का एक सुंदर पर्वतीय राज्य है। इस राज्य में तिब्बत का पठार पूर्वी दिशा में, जम्मू और कश्मीर उत्तर में तथा पंजाब पश्चिम में स्थित है। जबकि यह राज्य स्थलाकृति की विविधता और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के कारण अपने पड़ोसी राज्यों से एक दम अलग है। यहां फैली लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला के रेगिस्तान से लेकर देवदार के हरे भरे जंगल, सेब के बागीचों से लेकर सीढ़ीदार खेत, बर्फ से ढ़की चोटियों से लेकर गिरती बर्फ और लहराती नदियां सुंदरता को बढ़ाती है।यहीं स्थित है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुन्दर स्वच्छ अति रमणीय एवं प्रदेश की राजधानी शिमला।

शिमला की सैर

शिमला, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। वर्तमान में यह 1.6 लाख, केवल शिमला शहर के आसपास अपनी आबादी के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्य की राजधानी है। शिमला भारत और पाकिस्तान के बीच प्रसिद्ध शिमला संधि जो यहाँ हस्ताक्षर किए गए थे के रूप में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। जगह भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वास्तुशिल्प इमारतों, लकड़ी के शिल्प और सेब के लिए प्रसिद्ध है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी और ब्रिटिश कालीन समय में ग्रीष्म कालीन राजधानी शिमला राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है। यहां का नाम देवी श्यामला के नाम पर रखा गया है जो काली का अवतार है। शिमला लगभग 7267 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह अर्ध चक्र आकार में बसा हुआ है, जहां पूरे वर्ष ठण्डी हवाएं बहने का वरदान है। यहां घाटी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और महान हिमालय पर्वती की चोटियां चारों ओर दिखाई देती है। इसके उत्तर में बर्फ मानों क्षितिज तक जमी हुई है। यहां ठण्डी हवाएं बहती है और ओक तथा रोडोडेंड्रॉन के वनों से गुजरती हैं। शिमला का सुखद मौसम, आसानी से पहुंच और ढेरों आकर्षण इसे उत्तर भारत का एक सर्वाधिक लोकप्रिय पर्वतीय स्थान बना देते हैं। शिमला की खूबसूरती विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई आकर्षक खूबियां अपने आगोश में समेटे हुए है। वैसे तो शिमला जाने के लिए ट्रेन, हिमाचल प्रदेश की बसें, हवाई जहाज तथा अपने निजी वाहनों से भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। कालका - शिमला के बीच चलने वाली ट्रेन भी आकर्षक और सुन्दर है जो यात्रियों को शिमला पहुंचने में काफी आरामदायक साधन है।

शिमला की बात की जाए तो शिमला में ही घूमने के लिए कई जगह हैं। शिमला की माल रोड का नजारा सर्दियों में अनोखा ही है। यहां पर्यटकों को इस रोड पर काफी आनंद मिलता है। इस रोड पर खाने-पीने की चीजों के अलावा पहनने के लिए कपड़े, घुड़सवारी और फोटो सेशन के लिए कई सुन्दर जगह हैं। मालरोड पर स्थित चर्च देखने लायक है जो सदियों पुराना है। शिमला के आसपास भी घूमने लायक कई सुन्दर और रमणीक स्थल हैं जिन्हें बस देखते ही बनता है। इनमें चम्बा घाटी, डलहौजी पर्वतीय स्थान जो दुनिया की कई नई पुरानी चीजों से भरा पड़ा है। यहां राजशाही युग की भव्यता चारों ओर दिखाई देती है जो कई किलो मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

चम्बा घाटी

915 मीटर की ऊंचाई पर रवि नदी के दाएं किनारे पर स्थित है चम्बा घाटी। पुराने समय में राजशाही का राज्य होने के नाते यह लगभग एक शताब्दी पुराना राज्य है और 6वीं शताब्दी से इसका इतिहास मिलता है। यह अपनी भव्य वास्तुकला और अनेक रोमांचक यात्राओं के लिए एक आधार के तौर पर विख्यात है। ठण्ड के मौसम में ठण्डी हवाओं के कारण यहां का तापमान बहुत कम हो जाता है और इसलिए यहां भारी ऊनी कपड़ों की जरूरत नहीं है। यहां का मौसम गर्मी में अच्छा और खुशनुमा हो जाता है।

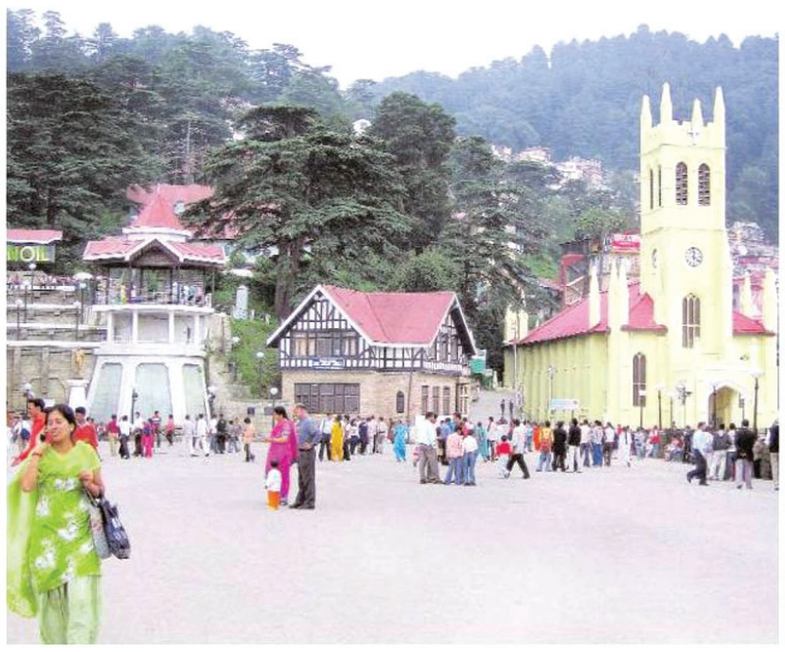

डलहौजी

पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में डलहौजी नामक यह पर्वतीय स्थान पुरानी दुनिया की चीजों से भरा पड़ा है और यहां राजशाही युग की भाव्यता बिखरी पड़ी है। यह लगभग 14 वर्ग किलो मीटर फैला है और यहां काठ लोग, पात्रे, तेहरा, बकरोटा और बलूम नामक 5 पहाड़ियां हैं। इसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गवर्नर जनरल, लॉड डलहौजी के नाम पर बनाया गया था। इस कस्बे की ऊंचाई लगभग 525 मीटर से 2378 मीटर तक है और इसके आस पास विविध प्रकार की वनस्पति पाइन, देवदार, ओक और फूलों से भरे हुए रोडो डेंड्रॉन पाए जाते हैं। डलहौज़ी में मनमोहक उपनिवेश युगीन वास्तुकला है जिसमें कुछ सुंदर गिरजाघर शामिल हैं। यह मैदानों के मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत करने के साथ एक लंबी रजत रेखा के समान दिखाई देने वाले रावी नदी के साथ एक अद्भुत दृश्य प्रदर्शित करता है जो घूम कर डलहौजी के नीचे जाती है। बर्फ से ढका हुआ धोलाधार पर्वत भी इस कस्बे से साफदिखाई देता है।

कुफरी

अनंत दूरी तक चलता आकाश, बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां और मीठे पानी के झरने, कुफरी में यह सब है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। यह पर्वतीय स्थान शिमला के पास समुद्री तल से 2510 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह आपको रोमांच और साहस की जादू भरी दुनिया में ले जाता है। कुफरी में ठण्ड के मौसम में अनेक खेलों का आयोजन किया जाता है जैसे स्काइंग और टोबोगेनिंग के साथ चढ़ाईयों पर चढ़ना। ठण्ड के मौसम में हर वर्ष खेल कार्निवाल आयोजित किए जाते हैं और यह उन पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है जो केवल इन्हें देखने के लिए यहां आते हैं। यह स्थान ट्रेकिंग और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भी जाना जाता है जो रोमांचकारी खेल प्रेमियों का आदर्श स्थान है।

मनाली

कुल्लू से उत्तर दिशा में केवल 40 किलो मीटर की दूरी पर लेह की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाटी के सिरे के पास मनाली स्थित है। यहां का परिदृश्य आपकी सांसें रोक लेता है। सबसे पहले आपको बर्फ से ढकी हुई पहाडियां, साफ पानी वाली व्यास नदी दिखाई देती है। दूसरी ओर देवदार और पाइन के पेड़, छोटे छोटे खेत और फलों के बागान दिखाई देते हैं। यह छुट्टियां बिताने के लिए आदर्श स्थान है और लाहुल, स्पीति, बारा भंगल, कांगड़ा और जनस्कर पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई करने वालों के लिए यह एक मनपसंद स्थान है। मंदिरों से अनोखी चीजों तक यहां से मनोरम दृश्य और रोमांचकारी गतिविधियां मनाली को हर मौसम और सभी प्रकार के यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाती हैं।

कुल्लू

कुल्लू घाटी को पहले कुलंथपीठ कहा जाता था। कुलंथपीठ का शाब्दिक अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। कुल्लू घाटी भारत में देवताओं की घाटी रही है। कुल्लू गर्मी के मौसम में लोगों का एक मनपसंद गंतव्य है। मैदानों में तपती धूप से बच कर लोग हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शरण लेते हैं। यहां के मंदिर, सेब के बागान और दशहरा हजारों पर्यटकों को कुल्लू की ओर आकर्षित करते हैं। यहां के स्थानीय हस्तशिल्प कुल्लू की सबसे बड़ी विशेषता है। कुल्लू में सुंदर पहाड़ियों और व्यास नदी के आस पास बनी हिल रिजॉर्ट में अवश्य जाएं।

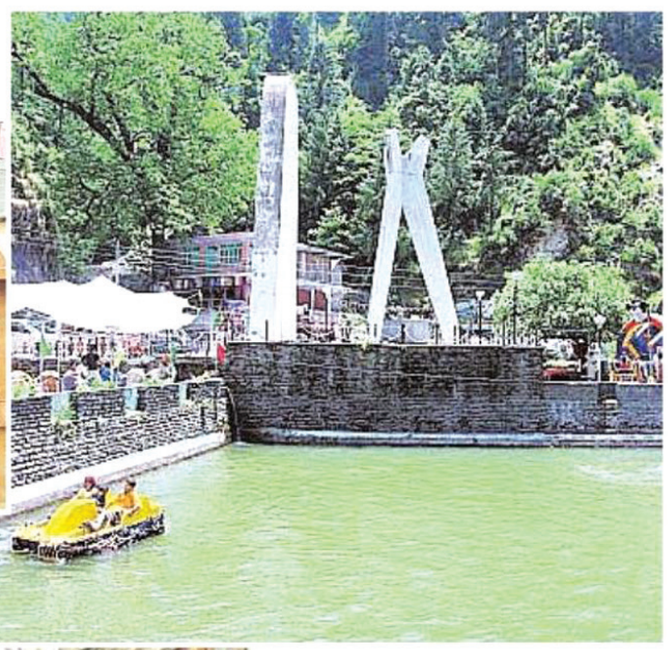

चैल

हिमालय की तराई में स्थित सबसे छोटे पर्वतीय स्थानों में से एक चैल, प्रकृति प्रेमियों और पक्षियों को देखने के शौकीन व्यक्तियों के लिए एक आदर्श स्थान है। समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मनोरम हरा भरा पर्वतीय स्थान शिमला के दक्षिण पूर्व में 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चैल घने पाइप और देवदार के जंगलों के बीच पृष्ठभूमि में बर्फ से ढकी हुई शिवालिक पहाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है। यहां 3 पहाड़ियों, राजगढ़ पहाड़ी के ऊपरी भाग में चैल का महल है, गांव में ही साध तिबा पहाड़ी और पंधेवा पहाड़ी स्नो व्यू मेंशन है। शिमला और कसौली हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख पर्वतीय

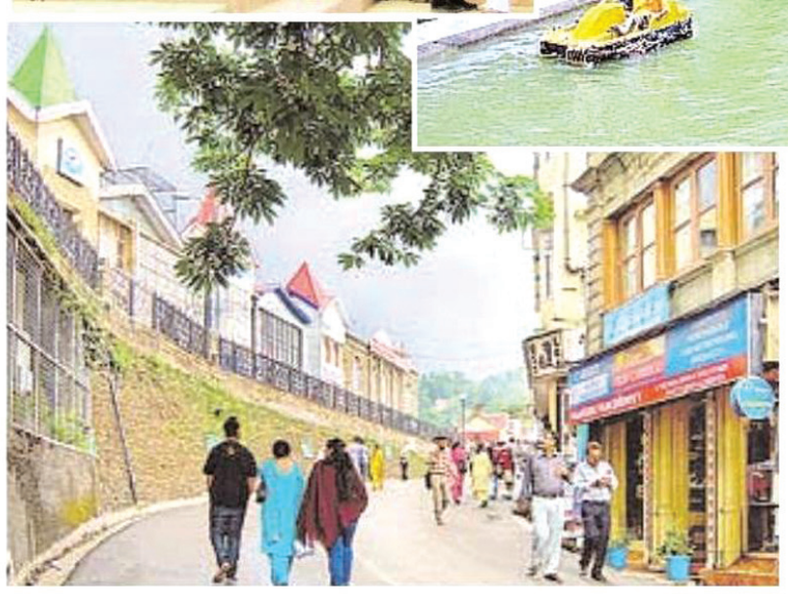

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी आज करगिल का दौरा करेंगे

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ के अनुसार, यह परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को 25वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर, सुबह नौ बज कर लगभग 20 मिनट पर करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएमओ ने कहा, ''प्रधानमंत्री वस्तुत: शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे।'' शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किमी लंबी दोहरी-ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण पूरा होने के बाद, यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी।

मानहानि मामले में राहुल गांधी आज अदालत में पेश होंगे

लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में 26 जुलाई को सुलतानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में हाजिर होंगे। कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बृहस्पतिवार को बताया कि राहुल गांधी 26 जुलाई को पूर्वाह्न नौ बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वह कार से सुलतानपुर के लिये रवाना होंगे और अदालत में पेश होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत दी थी।

केजरीवाल, सिसोदिया और कविता को कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब आठ अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के.कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था।

राबड़ी देवी पर ललन सिंह के बयान का राजद ने किया विरोध

पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सदन के अंदर और बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर जदयू सांसद सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के दिए बयान को लेकर राजद के सदस्यों ने विधान परिषद के अंदर हंगामा किया। वहीं राबड़ी देवी के नेतृत्व में परिषद के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया से जुड़े सवाल पर जदयू सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने हाल में एक टिप्पणी की थी जिसका विरोध राजद ने किया है। विधानपरिषद में भी राजद ने इसे मुद्दा बनाया और राबड़ी देवी पर जदयू सांसद ललन सिंह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया। राजद के सदस्य गुरुवार को विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान इस मुद्दे को लेकर हंगामा करते हुए वेल में आ गए।

हरियाणा कांग्रेस में एक-एक सीट पर 10 उम्मीदवार

चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए होड़ मची है। एक-एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं। अब तक कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 900 आवेदन आ चुके हैं। अभी 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। संभावना है कि यह आंकड़ा 1200 से पार जा सकता है। टिकट के लिए मची होड़ कांग्रेस को भारी भी पड़ सकती है। क्योंकि टिकट एक को ही मिलना है। ऐसे में कई मजबूत दावेदार या तो निर्दलीय तौर पर ताल ठोकेंगे या फिर दूसरे दलों के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने इस बार आवेदकों के लिए बाकायदा फीस निर्धारित की है। सामान्य जातियों के लिए 20 हजार रुपये, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए 5-5 हजार रुपये फीस तय की गई है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित (रिजर्व) हैं। खास बात ये है कि आरक्षित सीटों के लिए सबसे अधिक आवेदन आ रहे हैं।

राष्ट्रपति भवन के 'दरबार हॉल' और 'अशोक हॉल' का नाम बदला

नईदिल्ली। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित 'दरबार हॉल' और 'अशोक हॉल' के नाम को गुरुवार को बदल दिया गया। अब दरबार हॉल को 'गणतंत्र मंडप' और 'अशोक हॉल' को 'अशोक मंडप' के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, लोगों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार को प्रतिबिंबित करने वाला बनाने का लगातार प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से बताया गया, 'दरबार हॉल' और 'अशोक हॉल' का नाम बदलकर 'गणतंत्र मंडप' और 'अशोक मंडप' करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रसन्नता हुई।

भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र का प्रतीक और देश की एक अमूल्य धरोहर है। 'दरबार हॉल' राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों और कार्यक्रम के आयोजन का स्थान है। दरबार' शब्द भारतीय शासकों और ब्रिटिश अदालतों और सभाओं को संदर्भित करता है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद दरबार की प्रासंगिकता खत्म गई। 'गणतंत्र' की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है। 'गणतंत्र मंडप' आयोजन स्थल के लिए एक उपयुक्त नाम है। बयान के अनुसार 'अशोक' शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो 'सभी कष्टों से मुक्त' या 'किसी भी दुख से रहित' है तथा इसके अलावा, 'अशोक' का तात्पर्य एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से है। राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया, भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। इसके अनुसार, 'अशोक हॉल' का नाम बदलकर 'अशोक मंडप' रखा गया है। 'मंडप' भाषा में एकरूपता लाता है और 'अशोक' शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्यों को बरकरार रखते हुए अंग्रेजीकरण की संस्कृति के निशान को मिटाता है।

राष्ट्रपति भवन के हॉल का नाम बदलने पर प्रियंका का मोदी सरकार पर तंज

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल का नाम बदलने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि देश में शहंशाह की अवधारणा अभी भी मौजूद है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दरबार की कोई अवधारणा नहीं है बल्कि शहंशाह की अवधारणा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। इसके अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया। एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास, राष्ट्र का प्रतीक और लोगों की एक अमूल्य विरासत है। इसे लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रपति भवन के वातावरण को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार को प्रतिबिंबित करने वाला बनाने का लगातार प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमश: गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप करने पर प्रसन्न हैं। दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों का स्थान है। दरबार शब्द का तात्पर्य भारतीय शासकों और ब्रिटिशों की अदालतों और सभाओं से है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी प्रासंगिकता यानी गणतंत्र खो गई। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है, इसलिए गणतंत्र मंडप आयोजन स्थल के लिए एक उपयुक्त नाम है।

अशोक हॉल मूलत: एक बॉलरूम था। अशोक शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सभी कष्टों से मुक्त या किसी भी दु:ख से रहित है। इसके अलावा, अशोक का तात्पर्य एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है। यह शब्द अशोक वृक्ष को भी संदर्भित करता है जिसका भारतीय धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ कला और संस्कृति में भी गहरा महत्व है। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप करने से भाषा में एकरूपता आती है और कुंजी को बरकरार रखते हुए अंग्रेजीकरण के निशान दूर हो जाते हैं।

नीति आयोग की बैठक से ममता की भी दूरी!

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नीति आयोग सरकारी परिषद की बैठक में शामिल होने के बारे में प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के कुछ दिनों बाद, सूत्रों ने गुरुवार को संकेत दिया कि टीएमसी सुप्रीमो अब बैठक में शामिल नहीं हो सकती हैं, जिसकी अध्यक्षता शनिवार (27 जुलाई) को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों ने कहा कि चूंकि विपक्ष शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, ने पुष्टि की है कि वे बैठक में भाग नहीं लेंगे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बारे में अधिक जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है। यह ध्यान रखना उचित है कि नीति आयोग की बैठक से टीएमसी सुप्रीमो की अनुपस्थिति की अटकलें बनर्जी के बाद आई हैं, जिन्हें आज तीन दिवसीय यात्रा पर दिल्ली जाना था।

कांग्रेस नहीं दे रही साथ! इंडिया गठबंधन में अलग-थलग पड़े अरविंद केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए स्थितियां सहज होती दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं उनकी परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की गिरफ्तारी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बावजूद इसके वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर आज उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है।

इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के लिए स्वास्थ्य भी ठीक-ठाक नहीं चल रहा है जैसा कि उनकी पार्टी दावा कर रही है। पार्टी की ओर से केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। केजरीवाल का शुगर लगातार डाउन हो रहा है। उन्हें जेल में अच्छे से देखभाल नहीं मिल रही है। हालांकि भाजपा सभी आरोपी को खारिज करती दिखाई दे रही है। वही आम आदमी पार्टी को इंडिया ब्लॉक से काफी उम्मीदें भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक भी फिलहाल आम आदमी पार्टी का साथ देने के मूड में नहीं है।

ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंडिया ब्लॉक की बैठक में संजय सिंह और राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का मामला उठाया। राघव चड्ढा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता तिहाड़ जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलते रहे ताकि एक मैसेज जाएं कि पूरा विपक्ष केजरीवाल के साथ खड़ा है। दूसरी

ओर संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के सपोर्ट में इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया जाए। आप नेताओं की चाहत यह भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष संसद में मिलकर हंगामा करें। लेकिन दोनों ही मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक के अन्य गठबंधन सहयोगियों खास करके कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी को सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं।

दोनों ही मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक ने कहा कि हां इस मामले में देखते हैं। लेकिन तत्परता नहीं दिखाई दी। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को इंडिया ब्लॉक से वह सहायता नहीं मिल रहा है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। इंडिया ब्लॉक के लिए केजरीवाल के साथ परिस्थितियां इसलिए अलग हो चुकी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आप ने एकतरफा ऐलान करते हुए साफ तौर पर दावा कर दिया कि हम दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। यह बात कांग्रेस को बुरी लगी थी। कांग्रेस को भी पता है कि उसके लिए असली चुनौती अरविंद केजरीवाल ही हैं। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को ही सत्ता से हटकर केजरीवाल की पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई है।

केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो राहुल गांधी से ज्यादा मीडिया फूटेज उन्हें मिलेगी। ऐसे में कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों ने भी यह दावा किया था कि आप के साथ गठबंधन के बाद पार्टी कार्यकर्ता नाराज हुए। यही कारण है कि अब कांग्रेस संभल कर कदम उठा रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है। यही कारण है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अलग-अलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत-बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मैच आज

दांबुला। बांग्लादेश महिला टीम ने मुर्शिदा खातून (80) और कप्तान निगार सुल्ताना (नाबाद 62) के अर्धशतकों की बदौलत बुधवार को महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट मैच में मलयेशिया को 114 रन से पराजित कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया जिसमें उसका सामना 26 जुलाई को भारतीय टीम से होगा। वहीं, शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। श्रीलंका ने बुधवार को ग्रुप मैच में थाईलैंड को 51 गेंद रहते 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अगर सेमीफाइनल में भारतीय टीम बांग्लादेश को और पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को हराने में कामयाब रहती है तो महिला एशिया कप के फाइनल में महामुकाबला देखने को मिल सकता है।

भारतीय टीम नेपाल को 82 रन से हराकर और पाकिस्तान की टीम यूएई को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी। अब इन दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि, दोनों ही टीमें अपने विपक्षी को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगी। श्रीलंका की टीम जहां मजबूत मानी जाती है, वहीं बांग्लादेश की टीम भी उलटफेर करने में माहिर है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफाइनल 26 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर दो बजे से खेला जाएगा। वहीं, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दूसरा सेमीफाइनल उसी दिन शाम सात बजे से खेला जाएगा।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आठवां एशिया कप खिताब जीतने के मिशन पर है। उसने चार खिताब वनडे फॉर्मेट में और तीन खिताब टी20 फॉर्मेट में जीते हैं। महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई थी और टीम इंडिया तब चैंपियन बनी थी। यह नौवां संस्करण है और भारत सात बार (2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2016, 2022) खिताब जीत चुका है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में पांचवें दिन भी गिरावट, सेंसेक्स 109 अंक टूटा

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। ग्लोबल मार्केट में कमजोर रुख के बीच निवेशकों ने मेटल, बैंकिंग और फाइनैंशियल शेयरों में बिकवाली की। इंट्रा-डे ट्रेड में भारी गिरावट के बाद, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स टाटा मोटर्स और लार्सन एंड टुब्रो में तेजी के दम पर कुछ हद तक अपनी खोई हुई बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा और 109.08 अंक या 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,039.80 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 671 अंक या 0.83 प्रतिशत गिरकर 79,477.83 पर पहुंच गया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 7.40 अंक या 0.03 प्रतिशत गिरकर 24,406.10 पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 202.7 अंक या 0.83 प्रतिशत गिरकर 24,210.80 पर आ गया था। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में 17 शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

तेलंगाना सरकार ने 2.91 लाख करोड़ रु. का बजट पेश किया

हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.91 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ बजट पेश किया। बजट में राजस्व व्यय 2.21 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 33,487 करोड़ रुपये है। कुल राजस्व 2,90,814 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 57,000 करोड़ रुपये से अधिक के ओपन मार्केट लोन शामिल थे। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि के लिए 72,659 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग के लिए 21,292 करोड़ और सिंचाई के लिए 22,301 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। विक्रमार्क ने कहा कि इस बजट में हमने पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए 29,816 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।

नेस्ले इंडिया का मुनाफा जून तिमाही में 746.6 करोड़ पर पहुंचा

नईदिल्ली। दैनिक उपयोग की घरेलू वस्तुओं की कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड का अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ 6.9 प्रतिशत बढ़कर 746.60 करोड़ रुपये हो गया। नेस्ले इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी का पिछले साल अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ 698.34 करोड़ रुपये रहा था। समीक्षाधीन तिमाही में नेस्ले इंडिया की उत्पादों की बिक्री से आय 3.75 प्रतिशत बढ़कर 4,792.97 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 4,619.50 करोड़ रुपये थी। अप्रैल-जून तिमाही में कुल व्यय 2.7 प्रतिशत बढ़कर 3,844.01 करोड़ रुपये हो गया। अप्रैल-जून तिमाही में नेस्ले इंडिया की घरेलू बिक्री 4.24 प्रतिशत बढ़कर 4,608.50 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 4,420.77 करोड़ रुपये थी। इसकी कुल आय 3.64 प्रतिशत बढ़कर 4,853.07 करोड़ रुपये हो गई।

खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी वसूलने का कानूनी अधिकार

नई दिल्ली। कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को झटका देते हुए कहा है कि राज्यों के पास संविधान के तहत खदानों और खनिज वाली भूमि पर रॉयल्टी वसूलने का विधायी (कानूनी) अधिकार है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि खनिजों के बदले दी जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी और पीठ के सात न्यायाधीशों की ओर से फैसला पढ़ते हुए कहा कि संसद के पास संविधान की सूची दो की प्रविष्टि 50 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। संविधान की सूची-II की प्रविष्टि 50 खनिज विकास से संबंधित नियमों और खनिज अधिकारों पर करों से संबंधित है। इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने दो अलग-अलग फैसले दिये और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने इससे असहमति व्यक्त की।

क्या पेरिस में तोक्यो से ज्यादा चमकेंगे भारतीय

रौशन झा

पेरिस ओलिंपिक्स 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार भारतीय एथलीट्स के सामने चुनौती है अपना नया सर्वश्रेष्ठ कायम करने की। पिछली बार, तोक्यो ओलिंपिक्स में हमारे एथलीट्स ने इतिहास रचते हुए अब तक के सबसे ज्यादा सात मेडल जीते थे। इसके बाद, 2023 में आयोजित एशियन गेम्स में भी हमने शानदार प्रदर्शन किया और 100 से ज्यादा मेडल अपने नाम किए। इवेंट दर इवेंट भारतीय एथलीट्स के प्रदर्शन में लगातार सुधार दिख रहा है। इसलिए पूरा देश आस लगाए बैठा है कि हमारे खिलाड़ी तोक्यो से भी ज्यादा चमक पेरिस में बिखेरेंगे।

नीरज से उम्मीदें : जिस एक एथलीट से सबसे अधिक उम्मीदें लगाई गई हैं, वह हैं नीरज चोपड़ा। नीरज ने पिछली बार जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। तब एथलेटिक्स में पहली बार भारत के खाते में कोई मेडल आया था। नीरज इस समय शानदार फॉर्म में भी हैं। पिछले महीने फिनलैंड में उन्होंने 85.97 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। हर इवेंट में सफलता के झंडे गाड़ते चले आ रहे नीरज यह जरूर चाहेंगे कि पेरिस में भी वह गोल्ड जीतकर एक नया कीर्तिमान अपने नाम करें। ओलिंपिक्स में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में दो गोल्ड जीतने का कीर्तिमान, जो अभी तक किसी भारतीय के हिस्से नहीं आया है।

बैडमिंटन में दबदबा: बैडमिंटन में पिछले तीन आयोजन से लगातार भारत का खाता खुल रहा है। इन तीन में से दो मेडल पीवी सिंधु ने जीते हैं। हालांकि सिंधु का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन वह अच्छी तरह जानती हैं कि बड़े मंच पर किस तरह से अपना सर्वश्रेष्ठ देना है।

सिंधु के अलावा बैडमिंटन में मेंस डबल्स स्पर्धाओं में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी से भी बहुत उम्मीदें हैं। दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं और एक साथ मिलकर देश को कई मेडल दिला चुके हैं। लक्ष्य सेन भी पुरुष सिंगल्स में मेडल के दावेदारों में शामिल हैं।

कुश्ती पर भरोसा: 2008 पेइचिंग ओलिंपिक्स से हम रेसलिंग में लगातार मेडल जीत रहे हैं। इस क्रम को जारी रखने की जिम्मेदारी अनुभवी विनेश फोगाट पर होगी। विनेश तीसरी बार ओलिंपिक में खेलने उतरेंगी। वह जरूर चाहेंगी कि पिछले दिनों हुए विवादों का जवाब मेडल जीतकर दिया जाए। अंतिम पंघाल भी मेडल की प्रबल दावेदार हैं। पुरुष वर्ग में भारत के लिए इस बार केवल अमन सहरावत ही चुनौती पेश कर सकेंगे।

पंच दमदार: वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू पर देश को मेडल दिलाने का भार होगा। चानू ने पिछली बार सिल्वर जीता था। हालांकि तोक्यो ओलिंपिक्स के बाद से चानू का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। वह चोट से परेशान रही हैं। फिर भी वह अपने मेडल का रंग बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इसी तरह, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने पिछली बार ब्रॉन्ज जीता था। 2008 के बाद यह पहला मौका था जब बॉक्सिंग में हमने कोई मेडल जीता। इस बार लवलीना के साथ ही निखत जरीन का दावा भी मजबूत है। निखत पिछली बार ओलिंपिक्स में हिस्सा लेने से चूक गई थीं। कुछ ऐसा ही अमित पंघाल के साथ भी हुआ था। दोनों के पास अतीत की कसक मिटाने का मौका है।

हॉकी से आस: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2020 में ब्रॉन्ज जीतकर ओलिंपिक मेडल के चार दशक लंबे सूखे को खत्म किया था। ओलिंपिक्स में 8 गोल्ड जीतने वाली टीम इंडिया से उम्मीद है कि वह इस आंकड़े को इस बार 9 पर पहुंचाएगी।

मेडल पर निशाना: पेरिस में हमारे 117 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। शूटिंग में सबसे ज्यादा खिलाड़ी उतरेंगे। शूटिंग में हम व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गोल्ड भी जीत चुके हैं। टीम में शामिल कई खिलाड़ियों में मेडल पर निशाना लगाने की क्षमता है। इनमें कुछ नाम जो विशेष रूप से लिए जा सकते हैं, वो हैं- मनु भाकर, शिफ्त कौर समरा, अनीश भानवाला, ऐश्वर्य प्रताप तोमर, श्रेयसी सिंह।

अमृत 2.0 योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2541 करोड़ की 111 परियोजनाओं का अनुमोदन

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर मंत्री तोखन साहू ने दी जानकारी

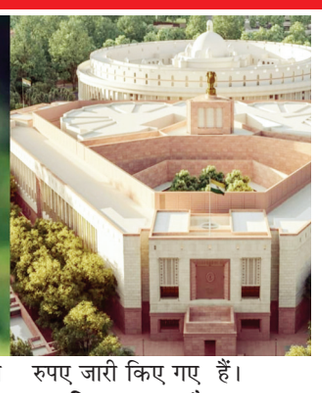

रायपुर। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 111 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। लोकसभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवालों का जवाब देते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि, छत्तीसगढ़ में 2541 करोड़ रुपए की 111 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है जिसमे से 18 परियोजनाओं के लिए 772.5 करोड़ रुपए प्रदत किए गए है और 1769 करोड़ रुपए लागत की 93 परियोजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ निविदा चरण में हैं।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय परिपथ के तहत जशपुर-कुनकुरी -मैनपाट- कमलेशपुर- महेशपुर कुरदार- सरोधदादर -गंगरेल- कोंडागांव- नथियानवगांव के विकास के लिए 94.23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

बिलासपुर और जगलपुर को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चिन्हित किया गया- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहा है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल पर पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी है। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ समिति संपूर्ण भारत में घरेलू पर्यटन 2020 कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच चुका है विदेशी पर्यटकों की संख्या भी इस वर्ष महामारी पूर्व के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय परिपथ के तहत जशपुर-कुनकुरी -मैनपाट- कमलेशपुर- महेशपुर कुरदार- सरोधदादर -गंगरेल- कोंडागांव- नथियानवगांव के विकास के लिए 94.23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत राज्य में बिलासपुर और जगलपुर को चिन्हित किया गया है।

अग्रवाल के सवाल पर जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री ने बताया कि देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और देश के भीतर नागरिकों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल शुरू की गई है। इतना ही नहीं बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित एवं उन्नत करना। पर्यटकों की सहायता के लिए देश भर से सूप प्रशिक्षित पेशेवर पर्यटक सुविधा कर्ताओं का समूह बनाकर ऑनलाइन शिक्षक मंच तैयार करना, 24म7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। विदेशी पर्यटकों के लिए ई वीजा पर्यटक, बिजनेस, मेडिकल, मेडिकल अटेंडेंट, कॉन्फ्रेंस समेत 7 श्रेणियों में प्रदान किया जा रहा है। मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देश में 14 थीम आधारित परिपथों के तहत 76 परियोजनाओं को 4865 हजार करोड़ रुपए जारी किए है।

भाजपा और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप: सुरेश ने लगाया जान से मारने का आरोप, अजय सिंह ने बताया निराधार

बीजापुर। जिला में कांग्रेस पदाधिकारी और भाजपा नेता के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ। एक ओर जहां कांग्रेस पदाधिकारी ने भाजपा नेता पर जान से मारने, जातिगत गाली-गलौज व गाड़ियां जलाने का आरोप लगाया है. वहीं भाजपा नेता ने कांग्रेस पदाधिकारी के आरोपों को झूठा और निराधार बताया।

दरअसल मंगलवार को माता मरई समाज के जिलाध्यक्ष व कांग्रेस के पदाधिकारी सुरेश चंद्राकर ने भाजपा नेता अजय सिंह पर विरूद्ध आरोप पत्र कलेक्टर अनुराग पाण्डेय को समाज के मौजूदगी में सौंपा और कार्रवाई की मांग की। चंद्राकर ने कहा कि भैरमगढ़ ब्लॉक के मिनिरल्स के तहत क्रेशर प्लांट मैं स्थापित कर रहा हूं, जिस पर भाजपा नेता अजय सिंह ने आपत्ति करते हुए मेरे वर्कर्स व इंजीनियर को जातिगत गाली गलौज,जान से मारने की धमकी व प्लांट में लगी गाड़ियों को आगजनी की बात कही।

वहीं भाजपा नेता अजय सिंह ने पत्रकार भवन बीजापुर में प्रेसवार्ता कर पूरे मामले को खंडन करते हुए कहा कि सुरेश चंद्राकर की ओर से मुझ पर लगाए गए सारे आरोप झूठ और निराधार है. इस आरोप में राजनीतिक की बू आ रही है. मुझ पर लगाए आरोप के सुरेश चंद्राकर सबूत दे। अगर वे प्रमाणित कर दे तो सरेंडर करने को तैयार हूं। भाजपा नेता अजय ने पूछा कि जब सुरेश की लड़ाई मुझसे तो समाज को बीच में क्यों लाया गया?

उन्होंने कहा कि कई व्यक्तिगत इंटरव्यू में सुरेश के अपने ही बयान में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें। आरोप साबित ना हुए तो संविधान के तहत झूठे आरोप के तहत सुरेश चंद्रकार पर कारवाई हो।

हर जिले में राजस्व विभाग के साथ बैठक करेंगे विधायक

सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की घोषणा

रायपुर। विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की मांग पर मंत्री ओपी चौधरी ने हर जिले में विधायकों के लिए राजस्व विभाग की बैठक कराने की घोषणा की। उनहोंने कहा कि, सभी जिलों में कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में पंजीयन गड़बड़ी की जांच कराने का भी ऐलान किया। दरअसल गुरुवार को सदन में बेलतरा से भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने जमीनों के पंजीयन के मामले में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। जवाब देते हुए वित्तमंत्र ओपी चौधरी बताया कि, गड़बड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्री विभाग में विजिलेंस सेल का गठन हुआ है। बड़े और विशेष केस की जांच विजिलेंस सेल करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि, प्रतिबंधित खसरों की पंजीयन रोकी गई है।

कोटवारी जमीन तक बिक्री हो गई – सुशांत शुक्ला

इस पर सुशांत शुक्ल ने कहा कि, प्रतिबंध के बावजूद कोटवारी जमीन की बिक्री हुई है। आधार, PAN वेरिफाई नहीं होता है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि, हम नया सिस्टम बना रहे हैं। PAN और आधार इंटीग्रेट होगा, कोटवारी जमीन की बिक्री हुई है तो परीक्षण कराएंगे।

मूणत ने उठाया कैश मांगने का मुद्दा

इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया- उन्होंने कहा कि, पंजीयन के समय चेक और ड्राफ्ट लेने से मना किया गया। कैश लिया गया, उसकी जानकारी दी जाए। इस पर मंत्री ने बताया कि, कैश पेमेंट की जानकारी उपलब्ध नहीं है। पिछली सरकार की गाइड लाइन रेट में 30% छूट खत्म हुई है। इससे भू अर्जन के समय किसानों को नुकसान होता था। बाजार और गाइड लाइन में अंतर से मिडिल क्लास को लोन नहीं मिल पाता था।

धर्मजीत ने रखा बैठक का सुझाव

इसके बाद भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, हर जिले में राजस्व की दिक्कत है। उन्होंने मांग रखी कि, हर जिले में विधायकों के लिए अधिकारी के साथ बैठक तय करवा दें। इस मंत्री ओपी चौधरी ने मामले में जांच टीम गठित कर मंत्री जांच की घोषणा की।

सक्ति जिले में खदानों की होगी जांच

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के सवाल पर मंत्री ओपी चौघरी ने सक्ति जिले में संचालित खदानों की जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि, सभी 19 डोलेमाइट खदानों की जांच अगले सत्र से पहले करा ली जाएगी।

सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर सदन में चर्चा

विभागों में तालमेल की कमी दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर सदन में चर्चा हुई. नियम 139 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताई और हेलमेट को अनिवार्य करने की बात कही. इस मामले को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में उठाया. उन्होंने कहा, परिवहन विभाग, स्थानीय शासन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और स्वास्थ्य विभाग जैसे विभागों में तालमेल की कमी भी सड़क हादसों में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है. अजय चंद्राकर ने कहा, 2023 की तुलना में 2024 की प्रथम तिमाही में 6323 सड़क दुर्घटना हुई है. आंकड़े बताते हैं कि करीब 20 लोगों की मृत्यु इस तरह की घटनाओं में रोजाना होती है. इस प्रदेश में 73.43 लाख वाहन पंजीकृत हैं. 18 लाख भारी वाहन हैं. पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क कितनी भार क्षमता के बनते हैं. सबसे ज़्यादा घटना की डेंसिटी यदि कोरबा, रायगढ़, रायपुर जैसे शहरों में है तो क्या यहां संचालित होने वाले उद्योगों पर उपकर लगाया जा सकता है? जनधन की क्षति कैसे रोकी जा सकती है. इस पर सदन एकमत हो सके. अजय चंद्राकर ने कहा, हिट एंड रन का मामला महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है. खराब सड़क, ओवर स्पीडिंग इस तरह की कार्रवाई को टालने राजनीतिक दबाव बनाया जाता है. दुर्घटना के बाद की स्थिति क्या है? घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिलना चाहिए. पहला पांच मिनट घायलों के लिए सबसे जरूरी होती है. सरकारी मदद का कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं होना. चार-पांच विभागों के मंत्रियों ने क्या बैठकर इस पर चर्चा की है. एक महत्वपूर्ण कारण है कि विभागों में आपस में तालमेल ना होना.

चंद्राकर ने आगे कहा, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में यातायात का सेटअप है? जब कोई वीआईपी मूवमेंट है तो देखा जाएगा, लेकिन जनसामान्य सड़क पर चल रहे हैं तब कौन देखेगा. ओवरलोडिंग चेकिंग त्यौहार है. शराब पीकर सड़क चलाना त्यौहार है. मैं भी तीन महीने के लिए गृहमंत्री था. हेलमेट अनिवार्य कर दिया था. हर रोज शाम को मेरे पास रिपोर्ट आती थी. मेरे साथ रेत खदान चलिए एक भी ओवरलोडिंग पर कार्रवाई नहीं होती. एक भी सरकारी ड्राइविंग स्कूल छत्तीसगढ़ में नहीं है. छत्तीसगढ़ में आज भी हार्वेस्टर चलाने के लिए पंजाब से ड्राइवर लाया जाता है. प्रदेशभर में ब्लैक स्पॉट है. इन ब्लैक स्पॉट को ख़त्म करने के लिए क्या इच्छाशक्ति है. क्या सीएसआर या डीएमएफ़ से ट्रामा यूनिट खोला जा सकता है? उन्होंने कहा, नया रायपुर के लिए एकीकृत ट्रैफ़िक कमांड बना सकते हैं, जहां ट्रैफ़िक नहीं है, लेकिन क्या रायगढ़ में ट्रैफ़िक कमांड सेण्टर बना सकते हैं? अजय चंद्राकर ने कहा, लाइसेंस करप्शन का ज़रिया ना बने.

लोकसभा में बृजमोहन ने देश के विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों से पूछे सवाल

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है कि, भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस कर भविष्य के लिए तैयार करना है। दरअसल रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी से पूछा था कि, सरकार ने युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने तथा नई नौकरियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। साथ ही पूछा था कि क्या सरकार स्किल इंडिया डिजिटल पहल के अंतर्गत नए डिजिटल पाठ्यक्रमों की योजना बना रही है। साथ ही सरकार द्वारा शुरू की गई कि स्किल इंडिया डिजिटल की मुख्य विशेषताएं एवं अन्य जानकारी मांगी थी। जिसपर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री ने बताया कि, स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रतिक्षण स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों और संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोनयन प्रतिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरुप बनाने तथा प्रशिक्षुओं की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार मांग को ध्यान में रखते विकसित किए जाते हैं। इतना ही नहीं भविष्य के लिए तैयार जॉब रोल, ड्रोन, कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई के तहत प्राथमिकता दी गई है। उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य की जॉब रोल की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

नक्सल पीड़ित के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

रायपुर। नक्सली हिंसा में मृतक के परिजनों को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी वर्गों के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर लाभांवित किया जा रहा है। आज बीजापुर जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों के 58 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कुल 58 पात्र आवेदकों को प्रथम चरण में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। पूर्व में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 19 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी, बाद में इस तिथि में वृद्धि करते हुए 24 जुलाई 2024 को निर्धारित की गई। उक्त तिथियों में प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण करते हुए समिति के निर्णय के आधार पर विभिन्न विभागों में चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से 58 आवेदक प्रथम चरण में पात्र पाए गए हैं. जिन्हें यह नियुक्ति दी जाएगी।

13 किलो गांजा के साथ अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बस स्टैंड भाठागांव गेट नंबर 01 के पास आरोपी शेख ईमरान को 13.530 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया। जप्त गांजे की कुल कीमत लगभग 2,70,000 रुपये है। आरोपी शेख ईमरान पिता शेख हारून, उम्र 28 वर्ष, निवासी खरबी बाबा ताज ले आउट, हाकिब पान ठेला के पास, थाना बाठोडा, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) को अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी गांजा को काटाभांजी (उड़ीसा) से नागपुर (महाराष्ट्र) लेकर जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा नशे के विरुद्ध निजात अभियान के तहत सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 25 जुलाई को थाना टिकरापारा पुलिस को सूचना मिली कि बस स्टैंड भाठागांव के पास एक व्यक्ति महरून रंग के सूटकेस में गांजा लेकर विक्रय करने की फिराक में है।

शादी के डर से घर छोड़कर भागी नाबालिग, आरपीएफ ने बचाया

रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों ने एक नाबालिग बालिका को सुरक्षित बचाया। बालिका को प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्थित महिला वेटिंग रूम के बाहर अकेले डरे-सहमे हालत में देखकर पुलिस ने उससे पूछताछ की। 24 जुलाई को उप निरीक्षक के.बी. गुप्ता, प्रधान आरक्षक पी.के. मेश्राम, प्रधान आरक्षक व्ही.सी. बंजारे, और आरक्षक एस.के. गिरी ने एक नाबालिग बालिका को प्लेटफार्म नंबर 1 पर अकेले और डरी हुई स्थिति में पाया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके परिवार वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। इस डर से कि घर लौटने पर परिवार वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा देंगे, वह घर से भाग आई थी। 17 वर्षीय बालिका ग्राम डाकडेरा, पोस्ट जुजुमुरा, थाना सिंदुरपंख, जिला संबलपुर (उड़ीसा) की रहने वाली है। उसने बताया कि वह 23 जुलाई को रात में रायपुर स्टेशन पहुंची थी और इससे पहले वह टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन पर थी। वह तीन दिनों से घर से निकली हुई थी। नाबालिग बालिका को अकेले यात्रा करना सुरक्षा कारणों से उचित नहीं समझा गया और उसकी घर न जाने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उसे मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार स्टेशन मास्टर रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, उसे अग्रिम कार्यवाही के लिए अध्यक्ष बाल कल्याण समिति रायपुर, छत्तीसगढ़ को सुपुर्द किया गया।

सुरक्षाबलों ने 5 नक्सलियों को पकड़ा

बीजापुर। सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षाबलों की टीम ने विस्फोटक के साथ 5 नक्सलियों को पकड़ा है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। दरअसल जिला में माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत् आज डीआरजी बीजापुर और थाना गंगालूर व फरसेगढ़ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सुरक्षाबलों की टीम ने पुसनार व सागमेटा से 5 माओवादियों को विस्फोटक के साथ पकड़ा है। माओवादियों के कब्जे से टिफिन बम, जिलेटिन स्टीक, माओवादी पर्चे, इलेक्ट्रिक,फ्यूज वायर आदि जब्त किए गए। पकड़े गए माओवादी आईईडी लगाने, मार्ग अवरूद्ध करने, पाम्पलेट बैनर लगाने की घटनाओं में शामिल थे। पकड़े गए नक्सलियों को थाना गंगालूर और फरसेगढ़ में वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय पेश किया गया।

सफाई, उद्यानों के रख-रखाव करेंगी स्व-सहायता समूह

रायपुर. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में रायपुर नगर निगम ने संबद्ध स्व-सहायता समूहों को अमृत मित्र के तौर पर नई पहचान दी है. उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के निर्देशन में रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला नगर निगम है, जिसने अमृत शहरों में स्व-सहायता समूहों को शुद्ध पेयजल प्रबंधन, जल संधारण, संरक्षण व जल उपयोगिता के संबंध में हर घर को जागरूक करने स्व-सहायता समूह के सदस्यों को फील्ड पर बड़ी जिम्मेदारी दी हैं. इन समूह सदस्यों को मानदेय देकर समूह को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी कदम बढ़ाने वाला रायपुर नगर निगम पहला निकाय है. नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के अनुसार रायपुर शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्धता की दिशा में नगर निगम काम कर रहा है. हर घर जल के बेहतर प्रबंधन से जुड़े, मितव्ययता के साथ जल संरक्षण व संवर्धन की दिशा में शासकीय प्रयासों में अपना साथ दें, इसके लिए जन जागरूकता की जिम्मेदारी नगर निगम से जुड़े स्व-सहायता समूह की दीदियों को दिया गया है. समूह की दीदियां उद्यानों के रख-रखाव में भी अपनी भूमिका निभाएंगी, साथ ही जल से जुड़ी हर गतिविधियों के संबंध में जागरूकता के विस्तार में अपना दायित्व निभाएंगी, इसके लिए मानदेय भी निर्धारित किया गया है.

तेंदूपत्ता सीजन 2024 में 36 हजार से अधिक संग्राहकों को 12 करोड़ रुपए से ज्यादा

बस्तर के हरा सोना संग्राहकों को बैंक मित्र एवं बैंक सखियों से सीधे मिल रही पारिश्रमिक राशि

रायपुर। बस्तर अंचल में तेंदूपत्ता को हरा सोना माना जाता है, जो वनांचल के संग्राहकों की अतिरिक्त आय का मुख्य जरिया है। गर्मी के दिनों में जब ग्रामीणों के पास न तो खेतों में काम होता है और न ही घर में कुछ काम, तब इसी तेंदूपत्ता यानी हरा सोना का संग्रहण उन्हें मेहनत एवं संग्रहण के आधार पर भरपूर पारिश्रमिक देता है। वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के लिये तेंदूपत्ता के प्रति मानक बोरा की दर में हुई वृद्धि भी खुशियां जगा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा तेंदूपत्ता का प्रति मानक बोरा राशि 5500 रुपए किए जाने के बाद संग्राहकों में अपार खुशी है। वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि स्थानीय स्तर पर बैंक सखियों के माध्यम से भुगतान होने के फलस्वरूप विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के संग्राहकों को बहुत सहूलियत हो रही है। इसे मद्देनजर रखते हुए बस्तर कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिले के अंदरूनी इलाके के संग्राहकों को तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि का भुगतान बैंक मित्र और बैंक सखियों के माध्यम से किया जा रहा है। तेंदूपत्ता सीजन 2024 में संग्रहित तेंदूपत्ता का 36 हजार 229 संग्राहकों को 12 करोड़ 43 लाख 95 हजार 749 रुपए पारिश्रमिक राशि अपने गांव के बैंक मित्र एवं बैंक सखियों द्वारा की जा रही है। लोहण्डीगुड़ा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम कुथर के तेंदूपत्ता संग्राहक आयतू और बैसू तेंदूपत्ता संग्रहण कर उसे समिति में बेचने का कार्य वर्षों से कर रहे हैं। एक सीजन में तीन से पांच से आठ हजार रूपए तक कमाई करने वाले इन संग्राहकों का कहना है कि वे सुबह से शाम तक पत्ते तोड़कर उसे गड्डी तैयार करते हैं, फिर फड़ में ले जाकर विक्रय करते हैं। उनका अधिकांश समय वन में ही गुजरता है। मुख्यमंत्री द्वारा 04 हजार रूपए प्रति मानक बोरा राशि की दर को 05 हजार 500 रूपए किए जाने पर खुशी जताते हुए बैसू ने कहा कि इससे उसके जैसे अनेक संग्राहकों को अच्छा लाभ मिला है। दरभा ब्लॉक के ग्राम पखनार की रहने वाली संग्राहक मासे मंडावी एवं सुकली मंडावी का कहना है कि वह कई साल से तेंदूपत्ता तोड़ने का कार्य कर रही है। संग्राहकों के हित में 4000 की राशि 5500 रूपए प्रति मानक बोरा होने पर गरीब संग्राहकों को इससे फायदा होने की बात कही। बकावंड ब्लॉक के डिमरापाल निवासी सुकरी नेताम ने बताया कि वह खेती-किसानी के साथ-साथ तेंदूपत्ता संग्रहण का काम कई वर्षों से कर रही हैं। गांव में तेंदूपत्ता संग्रहण से गर्मी के दिनों में कुछ कमाई हो जाती है।

विस मानसून सत्र : कोरोना काल के समय इस्तेमाल होने वाले मद में भ्रष्टाचार का आरोप, विधायक अनुज ने उठाया मुद्दा

रायपुर. भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने आज सदन में कोरोना काल के समय इस्तेमाल होने वाले मद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में जिलों को जो मद भेजा जाता था, वह कोरोना खत्म होने के बाद भी जारी है. यह बहुत बड़े स्केल में भ्रष्टाचार का प्रमाण है. सिर्फ कोटेशन के आधार पर करोड़ों की खरीदी की जा रही है. विधायक अनुज शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा, राज्य में कोविड महामारी के समय में राज्य शासन द्वारा संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिलों में आवश्यकतानुसार बजट का आबंटन औषधि-25007, कच्चा भार व्यावसायिक मद 10-009, मशीन उपकरण-28003, अनुरक्षण-24002 आदि मदों में किया गया था. उक्त बजट में से कुछ विशेष मदों का उपयोग कोविड महामारी में मांग/आश्यकतानुसार करने के लिए दिया गया था. इसके लिए कुछ विशिष्ट निर्धारित मदों के अंतर्गत बजट का आबंटन कर आवश्यकतानुसार सामाग्री क्रय किया जाना था, किंतु संचालनालय के बजट आबंटन शाखा में पदस्थ कुछ अधिकारी/कर्मचारी ने नियमों को अनदेखा करते हुए जिलों में अपने चहेते फर्मों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपनी मर्जी से उसे बजट का आवंटन करते थे, जो वर्तमान समय तक विद्यमान है. विधायक शर्मा ने कहा, वर्तमान में भी इन्ही मदों द्वारा फर्म विशेष को लाभ दिलाने के लिए बजट का आबंटन किया जा रहा है. यह भी ज्ञात हुआ है कि बजट का लाभ पाने वाले उक्त विशेष फर्मों में संचालनालय के कर्मचारी/अधिकारियों के करीबी रिश्तेदारों एवं जिले में पदस्थ फार्मासिस्ट के करीबियों की हिस्सेदारी है. इस मामले में समय-समय पर लगभग सभी विधायकों ने सवाल उठाए थे पर भी इस प्रकरण पर कठोर कार्रवाई नहीं होने से आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.